सुबह सवेरे

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 17 फरवरी, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 167, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

ओटीटी प्लेटफार्म : मनोरंजन की व्यक्तिगत क्रांति या सामूहिकता का अंत?

अरूण कुमार गोंड

अब संस्कृति अपने आप समाज से जन्म लेने वाली प्रक्रिया नहीं रह गई है; बल्कि वह एक बाजार द्वारा तय की जाने लगी है। भारतीय गांवों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना परंपरागत रूप से सामूहिकता, साझापन और सह-अस्तित्व पर आधारित रही है। तकनीकी साधनों के अभाव में, मनोरंजन का स्वरूप सामाजिक जुड़ाव का माध्यम रहा करता था।

उस समय देखने-सुनने की प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत गतिविधि नहीं थी, बल्कि सामूहिक अनुभव का उत्सव होती थी। अधिकांश ग्रामीण घरों में टीवी (टेलीविजन) उपलब्ध नहीं था और मोबाइल या इंटरनेट जैसी तकनीक भी सीमित थी। ऐसे में मनोरंजन एक साझा-सामाजिक घटना होता था, जो समाज में सामूहिक भावना और व्यक्तिगत तथा समूह के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक था।

परन्तु आज 'संस्कृति उद्योग' की अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म (ऐसी डिजिटल सेवाएं जो सीधे इंटरनेट के जरिये फिल्म, सीरीज या वीडियो पहुंचाती हैं) कैसे मनोरंजन से आगे बढ़कर एक पूरी व्यवस्था बन चुके हैं।

अब संस्कृति अपने आप समाज से जन्म लेने वाली प्रक्रिया नहीं रह गई है; बल्कि वह एक बाजार द्वारा तय की जाने लगी है। क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा यह सब अब लाभ, दर्शक संख्या और उपभोक्ता डेटा तय करते हैं।

समाजशास्त्री जिगमंट बॉमन की 'तरल आधुनिकता' के संदर्भ में देखें तो ओटीटी संस्कृति त्वरित संतुष्टि, बदलती पसंद और बिंज-वॉचिंग (एपिसोड खत्म होते ही अगला अपने-आप चलने लगे) जैसी आदतों को बढ़ावा देती है, जहां मनोरंजन टिकाऊ सामाजिक संबंधों की जगह क्षणिक उपभोग में बदल जाता है।

इसके उलट, अगर हम गांव के पुराने दृश्य को याद करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। गांव के कुछ ही घरों में टीवी हुआ करती थी; अधिकतर काले-सफेद स्क्रीन वाली, जिसके ऊपर एंटीना लगा रहता था और हवा या मौसम के साथ तस्वीर साफ-धुंधली होती रहती थी। शाम होते ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में एक ही उत्साह होता 'आज वाला सीरियल/एपिसोड देखना है।'

जैसे ही टीवी ऑन होता, आस-पास के घरों से लोग धीरे-धीरे उसी आँगन या बरामदे में इकट्ठा होने लगते। जमीन पर बोरी, दरी या चटाई बिछ जाती; जगह कम पड़ती तो कोई खिड़की के बाहर खड़े होकर भी देख लेता। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि साथ बैठने, साथ हंसने और साथ प्रतिक्रिया देने का एक साझा अनुभव था। उस समय देखने की क्रिया समाज में व्यक्ति और समूह के बीच एक सहज संतुलन बनाती थी; जो आज की व्यक्तिगत स्क्रीन संस्कृति में धीरे-धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है।

आज जब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को पूरी तरह व्यक्तिगत बना दिया है, तब यह पुराने अनुभव और भी मूल्यवान लगते हैं। आज भले ही हमारे पास ओटीटी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मोबाइल स्क्रीनें, एक जीबी डाटा प्रतिदिन, और अनगिनत विकल्प हों, लेकिन उस समय की सामूहिकता, साझापन, और मानवीय जुड़ाव आज की किसी भी तकनीक से बड़ा 'मनोरंजन' था।

आज ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस परंपरा को बदल दिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार किसी भी समय कंटेंट देख सकता है। इस सुविधा ने मनोरंजन को व्यक्तिगत बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही पारिवारिक और सामूहिक अनुभवों की कमी भी बढ़ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म इसी बदलाव का प्रतीक हैं। गांव और कस्बों में लोग अब अपनी स्क्रीन पर अपने अनुसार मनोरंजन का चयन करते हैं, जिससे पारंपरिक सामूहिकता का स्थान व्यक्तिगत अनुभव ने ले लिया है।

एक कथन है कि 'मीडिया ही संदेश है।' अर्थात् ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म दर्शकों को वैश्विक कंटेंट तक सीधे पहुंच प्रदान करता है- कोरियाई ड्रामा, अमेरिकी वेब सीरीज, यूरोपीय डॉक्यूमेंट्री और भारतीय स्थानीय सामग्री। यह सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन पारंपरिक मनोरंजन और स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं पर इसका प्रभाव भी स्पष्ट है। पहले जो सामूहिक अनुभव एक घर के आंगन या बरामदे में साझा भावनाओं के माध्यम से बनता था, अब वह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की निजी दुनिया में सीमित हो गया है।

देखा जाये तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म उपभोग की संस्कृति को बढ़ावा देता है। युवा पीढ़ी अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट का चयन करती है, जिससे मनोरंजन न केवल देखना बल्कि पहचान, प्राथमिकता और जीवनशैली की अभिव्यक्ति बन गया है। तथा आधुनिक समाज में व्यक्तिगतता और सामाजिक दूरी बढ़ती है। ओटीटी इस दूरी को और अधिक बढ़ाता है, क्योंकि लोग पारिवारिक या पड़ोसी संवाद की बजाय अपने कमरों और निजी स्क्रीन में खो जाते हैं।

फिर भी, ओटीटी का सकारात्मक पहलू यह है कि नई प्रकार की डिजिटल सामूहिकता का अवसर प्रदान होता है। सोशल-मीडिया, ऑनलाइन फोरम और कमेंट सेक्शन के माध्यम से लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनते हैं।

सामाजिक दृष्टि से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रभाव द्विविध प्रकृति का है। एक ओर यह ज्ञान, वैश्विक दृष्टि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाता है; दूसरी ओर यह पारंपरिक सामूहिक अनुभव, पारिवारिक संवाद और स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं को कमजोर कर रहा है।

कस्टमाइजेशन और दर्शक की पसंद के अनुसार सामग्री की सिफ़ारिश ओटीटी का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई है। परिणामस्वरूप, दर्शक जल्दी से जल्दी अच्छा कंटेंट देख पाते हैं, अधिक सामग्री का उपभोग करते हैं, और फिल्म देखने का अनुभव नए तरीकों से परिभाषित होता है। अब न केवल साप्ताहिक बल्कि रोज़ाना या दैनिक रिलीज़ भी आम हो गई हैं, जिससे मनोरंजन का निरंतर प्रवाह बनता है।

देखा जाये तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने मनोरंजन को व्यक्तिगत, सहज और वैश्विक बना दिया है। यह दर्शकों को अपनी पसंद और जीवनशैली के अनुसार अनुभव चुनने का अवसर देता है। साथ ही, यह मीडिया उद्योग और संस्कृति उद्योग के विस्तार तथा नए बाजारों तक पहुँचने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। इस तरह, ओटीटी केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि समाज के मनोरंजन, संस्कृति और व्यवहार को नया आकार देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है।

('डाउन टू अर्थ' हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026'

पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का किया उद्घाटन

- 300 से ज्यादा कंपनियां दिखा रहीं एडवांस गैजेट्स; खेती, पढ़ाई और सेहत पर फोकस रहेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में आज 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल हुए स्टार्टअप्स के पवेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली।

ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ-साथ 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026' का भी आयोजन किया जा रहा है। यहां दुनियाभर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगे। यहां आम लोग देख सकेंगे कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है।

पीएम मोदी बोले- दुनियाभर से आए लोगों का स्वागत- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि आज से दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया 'आई इम्पैक्ट समिट' शुरू हो रही है। मैं इस समिट में हिस्सा लेने आए दुनिया भर के नेताओं, बड़े बिजनेसमैन, इनोवेटर्स, पॉलिसी बनाने वालों, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी के जानकारों का दिल से स्वागत करता हूं। इस समिट की थीम 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' यानी 'सबका भला और सबकी खुशी' है। यह इंसानियत की तरक्की के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने के हमारे साझा संकल्प को दिखाती है।

सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और मुकेश अंबानी सहित 40+ सीईओ पहुँचेगें- समिट में 100 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा सहित 15-20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 50 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे।

उप्र में 1.56 लाख शिक्षा मित्र-अनुदेशकों की सैलरी बढ़ेगी

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। सीएम योगी ने कहा- शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा कार्यकत्रियों की सैलरी हम बढ़ाएंगे। निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ाने जा रहे हैं। कोई भी शिक्षक हो, हम लोगों ने इनको 5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 1 अप्रैल से यह लागू भी हो जाएगा।

यूपी में 1.47 लाख शिक्षामित्र और 28 हजार से अधिक अनुदेशक हैं। सरकार करीब 9 साल बाद मानदेय बढ़ाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मित्र और अनुदेशक के मानदेय में 2 हजार रुपए महीने की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों की समस्या का विधिक समाधान करने का वादा किया था।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल का विधानसभा में बजट अभिभाषण, हंगामा

बजट सत्र की शुरुआत, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की नारेबाजी

फोटो : प्रवीण वाजपेई

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से हंगामेदार शुरुआत हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण छह छंदों में वंदे मातरम् का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। साथ ही संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी भी दी। सदन में विभिन्न हस्तियों और नेताओं के निधन पर पक्ष-विपक्ष के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल के म.प्र. विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार भी मौजूद थे।

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा-

राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश ऐसी दहलीज पर खड़ा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने, पीएम जनमन योजना के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया।

शरद की सुबह

तुम अपनी दो आँखों से देखती हो एक दृश्य
दो हाथों से करती हो एक काम
दो पाँवों से
दो रास्तों पर नहीं एक ही पर चलती हो
सुनो चारुशीला!
एक रंग और एक रंग मिलकर
एक ही रंग होता है
एक बादल और एक बादल
मिलकर एक ही बादल होता है
एक नदी और एक नदी मिलकर
एक ही नदी होती है
नदी नहीं होंगे हम
बादल नहीं होंगे हम
रंग नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे
अच्छा ज़रा सोचकर बताओ
कि एक मैं और तुम मिलकर कितने हुए
क्या कोई बता सकता है
कि तुम्हारे बिन मेरी एक वसंत ऋतु
कितने फूलों से बन सकती है
और अगर तुम हो तो क्या मैं बना नहीं सकता
एक तारे से अपना आकाश।

-नरेश सक्सेना

थोक महंगाई 10 महीने में सबसे ज्यादा

- जनवरी में बढ़कर 1.81 प्रतिशत पर पहुंची, खाने-पीने की चीजें महंगी हुईं

नई दिल्ली (एजेंसी)। जनवरी में थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई) बढ़कर 1.81 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83 प्रतिशत पर थी। ये 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 को ये 2.05 प्रतिशत पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आज यानी 16 फरवरी को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं।

रोजाना जरूरत के सामान हुए महंगे- रोजाना की जरूरत वाले सामानों (प्राइमरी आर्टिकल्स) की महंगाई 0.21 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई। खाने-पीने की चीजों (फूड इंडेक्स) की महंगाई माइनस 0.43 प्रतिशत से बढ़कर 1.55 प्रतिशत हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर माइनस 2.31 प्रतिशत से घटकर माइनस 4.01 रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 1.82 प्रतिशत से बढ़कर 2.86 प्रतिशत रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक

प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को किया जाए प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के दिशा में हो रहे बेहतर कार्य के परिणाम स्वरूप प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में मानव-वन्य जीव सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए जनता को जागरूक करने तथा उन्हें आवश्यक सतर्कता बरतने के उपायों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग से समन्वय करते हुए प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से परिचित कराने के लिए संचालित किऐ जा रहे अनुभूति कार्यक्रम का विस्तार करने और इस गतिविधि में अधिक से अधिक शालाओं को शामिल करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की मंत्रालय में हुई 31वीं बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में वन राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव वन श्री संदीप यादव सहित वन विभाग के अधिकारी और वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को वन्य जीव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बदले में उन राज्यों से भी वन्य जीव मध्यप्रदेश लाए जाएं। इससे प्रदेश में वन्य जीवों की विविधता बढ़ेगी। उन्होंने वन्य जीव प्रबंधन में अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और बेस्ट प्रेक्टिसेस को अपनाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को जोड़कर वन और वन्य जीव के संबंध में अध्ययन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में विद्यमान पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण की श्रेष्ठ व्यवस्था हो, वन और पुरातत्व विभाग तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की कार्यशाला भी आयोजित की जाए। बैठक में प्रदेश में बढ़ रही हाथियों की संख्या को दृष्टिगत करते हुए हाथियों पर केंद्रित पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के संबंध में चर्चा हुई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरू श्री विजय मनोहर तिवारी ने हाथी प्रबंधन पर विश्वविद्यालय द्वारा आलेख लेखन का प्रस्ताव रखा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सर्पदंश की घटनाओं में प्रभावितों की जान बचाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 व्यक्तियों को सांप पकड़ने तथा प्रभावित को बचाने के लिए प्रारंभिक रूप में सहायता करने संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। सांपों के संबंध में आवश्यक जागरूकता और सर्तकता बरतने के उपायों का भी प्रचार-प्रसार आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉग स्क्वाड में देशी नस्ल के डॉग शामिल करने के लिए भी पहल करने के निर्देश दिए।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 17 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

रक्षामंत्री राजनाथ ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को दिया चैलेंज?

- हमें 5 साल में वो करना है, जो दूसरे देश 20 साल में करते हैं

नईदिल्ली (एजेंसी)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि देश एडवांस्ड मीडियम कॉम्बेट एयरक्राफ्ट यानी एमका के डिजाइन और डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पूर्व में भी एयरो इंजन के क्षेत्र में महारथ हासिल करने के कई प्रयास किए हैं। अब समय आ गया है कि हमारे जो प्रयास अधूरे रह गए थें, उनको हम पूरा करें।

रक्षा मंत्री सोमवार को गैस टरबाइन रिसर्च स्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में विशेषज्ञों के बीच बोल रहे थे। रक्षामंत्री ने विशेषज्ञों व शोधकर्ताओं से कहा, अगर किसी इंजन को विकसित करने में 25 साल लग रहे हैं, तो भारत की मौजूदा स्थिति , हमारी रणनीतिक जरूरत और हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी हैं कि आप मानकर चलिए कि आपके 20 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ 5 साल ही आपके पास बचे हैं।

जम्मू-कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट फिर से खोले गए

- पहलगाम हमले के बाद से बंद थे, पिछले साल सितंबर में भी 7 खुल चुके

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में बंद 14 टूरिस्ट स्पॉट को फिर से खोलने का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पूरी सिक्योरिटी रिव्यू और चर्चा के बाद मैंने कश्मीर और जम्मू डिवीजन में और टूरिस्ट स्पॉट फिर से खोलने का ऑर्डर दिया है।

कश्मीर डिवीजन में 11 टूरिस्ट स्पॉट - यूसमर्ग, बडगाम में दूधपथरी, कोकरनाग में दांडीपोरा पार्क, पीर की गली, शोपियां में दुबजान और पड़पावन, श्रीनगर में अस्तनपोरा, ट्यूलिप गार्डन, थजवास ग्लेशियर, गंदेरबल में हंग पार्क और बारामूला में वुलर/वतलाब को फिर से खोला जाएगा। वहीं जम्मू डिवीजन में 3 टूरिस्ट स्पॉट- रियासी में देवी पिंडी, रामबन में माहू मंगत और किश्तवाड़ में मुगल मैदान आम पब्लिक के लिए ओपन होंगे। घूमने वाली इन जगहों को पिछले साल अप्रैल में हुए पहलगाम अटैक के बाद से बंद कर दिया गया था।

राजस्थान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका

8 लोग जिंदा जले, 4 गंभीर

पॉलीथिन में ले जाने पड़े शव, मैनेजर हिरासत में, फैक्ट्री सीज

जयपुर/भिवाड़ी (एजेंसी)। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। वहीं सीएम भजनलाल और पीएम मोदी इस दुखद घटना पर गहरा शोक जता कर परिवार को आर्थिक सहायता का भरोसा दिलाया।

शव बुरी तरह जल गए थे। कई शवों के कंकाल भर बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथिन में इकट्ठा किया। हादसा खुशखेड़ा कारौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ। फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। फैक्ट्री को सीज कर दिया है। तीन मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के मिंटू, नितेश और सुजान के रूप में हुई है। अन्य मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा।

पीएम, सीएम ने जताया गहरा दुख

हादसा खुशखेड़ा कारौली इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे।

शव बुरी तरह जल गए थे। कई शवों के कंकाल भर बचे थे। बॉडी पार्ट्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथिन में इकट्ठा किया।कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने कहा- देखकर लग रहा है कि छोटा एक्सप्लोसिव मटेरियल था। गैस रिसाव नहीं था।एडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार, फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र है। उन्होंने किसी तिवारी को यह फैक्ट्री लीज पर दी थी।

रेस्क्यू टीम को केमिकल फैक्ट्री के अंदर से पटाखे और बारूद मिला है। कहा जा रहा है कि यहां अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सीएम भजनलाल ने कहा- राहत, बचाव कार्य के निर्देश दिए गए,समाचार अत्यंत दुःखद है

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दु :खद है। जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

फरीदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 35 लोग झुलसे

फरीदाबाद (एजेंसी)। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बड़ी खबर है। जिले के मुजेसर थाना क्षेत्र के सेक्टर 24 में सोमवार शाम को एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में दो पुलिसकर्मी समेत 35 से अधिक कर्मचारी झुलस गए। सभी घायलों में से 12 को बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि बाकी 23 को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से दो की हालत गंभी बताई जा रही है।जानकारी के मुताबिक, यह घटना सोमवार शाम चार बजे के बाद की है। बताया गया है कि फैक्ट्री में मेटल शीट कटिंग का काम होता है। इसके लिए सीएनसी मशीनें लगी हैं। शाम के समय जब कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी वहां रखे एक केमिकल ड्रम में अचानक धमाका हो गया। इसके बाद एक के बाद एक कई ड्रम फटते चले गए। इससे आग लग गई और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई।

भुवनेश्वर में छत पर धमाका, बदला लेने के लिए बम बना रहा था परिवार

4 लोग बुरी तरह झुलसे, दो की मौत

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के आजाद नगर में 27 जनवरी को एक घर की छत पर जोरदार धमाका हुआ। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, मां-बेटा सहित 4 लोग किसी से बदला लेने के लिए छत पर बम बना रहे थे। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया।

इससे चारों लोग बुरी तरह झुलस गए। इनमें दो की मौत हो गई है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें दिखा की छत पर 4 पानी की टंकियां लाइन से रखी हैं। टंकियों के पीछे अचानक से धमाके के साथ धुएं का गुबार उठा। फिर झुलसे लोग एक-एक कर भागते नजर आए।

घायल हुए लोगों की पहचान शहनवाज मलिक (26), उसकी मां लिलातुन बीबी, मंगेतर तृप्तिमयी महल (23) और दोस्त अमीया मल्लिक (27) के रूप में हुई। शहनवाज मलिक और उसकी मां की मौत हो गई है। वहीं दो अन्य अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहनवाज एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी होता है। उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। वह किसी बदला लेने की नियत से छत पर देसी बम बना रहा था। उस वक्त पर परिवार के सदस्य भी उसके पास ही मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट हैरान होकर बोला

शादी से पहले फिजिकल होना समझ से बाहर

लड़का-लड़की अजनबी होते हैं, हम पुराने ख्यालों वाले लेकिन भरोसा करने से पहले सावधान रहें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपों से जुड़े एक मामले में शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर हैरानी जताई। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि हम यह नहीं समझ पाते कि एक लड़का और लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा- हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। शादी से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।

जस्टिस नागरत्ना के साथ जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर एक महिला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। आरोप है कि व्यक्ति पहले से शादीशुदा था और बाद में उसने दूसरी महिला से शादी कर ली।

क्या है पूरा मामला?

सरकारी वकील के मुताबिक, लगभग 30 साल की युवती की 2022 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर शख्स से मुलाकात हुई थी। आरोप है कि शख्स ने युवती से शादी का वादा करके दिल्ली और बाद में दुबई में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

युवती ने दावा किया है कि शख्स के कहने पर वह दुबई गई थी। वहां उसकी सहमति के बिना आरोपी ने अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए, और विरोध करने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि शख्स ने 19 जनवरी, 2024 को पंजाब में दूसरी शादी कर ली थी।

इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी की तरफ से किया गया शादी का वादा शुरू से ही झूठा था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा था। हाईकोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

राज्यपाल बड़वानी के ग्राम नागलवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

दीन-दुखियों की सेवा का संकल्प प्रेरणादायी और अनुकरणीय : राज्यपाल

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि दीन-दुखियों की सेवा का संकल्प प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। खरगौन-बड़वानी सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने माता-पिता के संस्कारों से प्रेरित होकर जो सेवा का संकल्प लिया है, वह अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने सुशीला देवी उमराव सिंह पटेल सेवा संस्थान द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिये निरंतर किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

राज्यपाल पटेल बड़वानी के भिलट देव धाम, ग्राम नागलवाड़ी में सुशीला देवी उमरावसिंह पटेल सेवा संस्थान द्वारा सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन एवं टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं पोषण आहार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम से पूर्व स्थानीय भिलट देव धाम पहुँचकर पूजा-अर्चना भी की।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि संस्था द्वारा टी.बी. रोगियों को पोषण आहार वितरण, सिकल सेल जांच, व्यापक जागरूकता तथा विभिन्न प्रकार की जांच-परामर्श आदि सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करना गरीब, वंचित और जरूरतमंदों की बड़ी मदद है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।

'हर ग्राम-एक काम' जनकल्याण की सार्थक पहल

राज्यपाल श्री पटेल ने इस अवसर पर सांसद अभियान अंतर्गत 'हर ग्राम-एक काम' का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक पंचायत में केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के माध्यम से जनकल्याणकारी कार्य करना सार्थक पहल है। यह अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ प्रभावी रूप से पहुँचाने का विशेष प्रयास है। राज्यपाल श्री पटेल को बताया गया कि अभियान में सांसद प्रत्येक पंचायत में युवाओं, महिलाओं एवं नागरिकों से संवाद करेंगे। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों एवं नवीन अवसरों का सृजन करेंगे। स्वरोजगार-रोजगार के नवाचार करेंगे। स्थानीय उद्योगों एवं लघु व्यवसायों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में सिकल सेल मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र योजना के टी.बी. मरीजों को पोषण आहार वितरित किया। स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा हृदय रोग, कैंसर, स्त्री रोग, स्तन कैंसर, नाक-कान-गला, हड्डी रोग, शिशु रोग, मूत्र रोग, नेत्र रोग एवं जनरल मेडिसिन संबंधी परामर्श प्रदान किया गया। ईको, ई.सी.जी., शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद एवं नेत्र परीक्षण, सर्वाइकल कैंसर, कोल्पोस्कोपी, पैप स्मियर तथा मैमोग्राफी आदि जांचें भी की गईं।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंतरसिंह आर्य, सांसद रतलाम-झाबुआ श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष बड़वानी श्री बलवंतसिंह पटेल, पूर्व मंत्री प्रेमसिंह पटेल सहित श्रीमती नंदा ब्राह्मणे, श्री अजय यादव, संस्था अध्यक्ष श्रीमती बसंती गजेंद्रसिंह पटेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, चिकित्सक, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में खरगोन-बड़वानी संसदीय क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे।

विक्रमोत्सव

प्रीतम की अप्रतिम स्वर लहरियों से महादेव की आराधना

उज्जैन से डॉ. जफर महमूद

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वर्षों पहले सम्राट विक्रमादित्य के वैभव की गाथा को आत्मसात कर विक्रमोत्सव की परिकल्पना प्रस्तुत कर दी थी। इसी परिकल्पना को साकार करते हुए सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान ने उज्जैन में महाशिवरात्रि की सुबह कलश स्थापना से विक्रमोत्सव का शुभारंभ किया। महाशिवरात्रि की संध्या में देवाधिदेव भगवान महादेव की पावन भूमि उज्जयिनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कला एवं संस्कृति के विराट उत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि विक्रमोत्सव देश दुनिया में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का एक

अनूठा उत्सव बन चुका है। शुभारंभ संध्या पूर्व रंग में देश के प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम की अद्भुत शिवोउहम प्रस्तुति ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। प्रीतम की अप्रतिम गीत, संगीत और भजन की प्रस्तुतियों ने महोत्सव को अलौकिक आध्यात्मिक और दिव्य स्वरों से गूंजायमान कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने असंख्य श्रोताओं को सम्राट विक्रमादित्य और उनके स्वर्णिम काल को याद करते हुए एक करोड़ एक लाख रुपए रुपये के सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही 21 लाख रुपए का राष्ट्रीय सम्मान और पांच-पांच लाख के तीन राज्य स्तरीय सम्मान दिए जाने की बात कही। विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक एवं मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव के अंतर्गत 41 से अधिक बहुआयामी गतिविधियों में 4000 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

महिला को 13 बार चाकू से गोदा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक महिला की चाकू मार हत्या कर दी गई। आरोपी ने 13 बार वार किए। इनमें 9 सीने, 3 पेट और एक गर्दन पर लगा। इसके बाद आरोपी ने भी ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। महिला आरोपी पर पिछले 6 महीने से घर छोड़ने का दबाव बना रही थी, इसी के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना गौतम नगर थाना इलाके में सोमवार शाम 5 बजे की है। परिजनों का कहना है कि आरोपी महिला का गुरु भाई था। वह अपने 3 बच्चों की हत्या के मामले में सजा काट चुका है। पिछले साल ही जेल से छूटा था। तब से वह यही आकर रहा था।

भेल टीआरएम विभाग में लगी आग पर काबू पाया

भोपाल (नप्र)। भोपाल की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फैक्ट्री की एक यूनिट में सोमवार को आग लग गई। यूनिट के ऊपरी हिस्से में अचानक धुआं निकलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि, भेल प्रबंधन ने तुरंत अपनी दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया।

मणिशंकर अय्यर बोले-

मैं गांधीवादी-नेहरूवादी हूं, राहुलवादी नहीं

- पवन खेड़ा को जयराम रमेश का तोता बताया ,थरूर विदेश मंत्री बनना चाहते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने सोमवार को कहा कि इंडी ब्लॉक को मजबूत करने के लिए एमके स्टालिन सबसे सही नेता हैं, जबकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अय्यर ने कहा कि राहुल भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूं। इसलिए मैं गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हूं लेकिन राहुलवादी नहीं हूं। अय्यर ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर एंटी-पाकिस्तान हैं। वे अगले विदेश मंत्री बनना चाहते हैं। अय्यर ने पवन खेड़ा को प्रवक्ता की जगह तोता बताया। उन्होंने कहा- पवन खेड़ा वही दोहराते हैं, जो जयराम रमेश उन्हें बताते हैं। इसके बाद पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा- मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है।

परिक्रमा

सेवातीर्थ में प्रवेश और चार अहम् फैसले करते मोदी

अरुण पटेल

लेखक सुबह सबेरे के प्रबंध संपादक हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 फरवरी को नई दिल्ली में अपने प्रशासनिक परिसर सेवातीर्थ का अनावरण कर उसमें बैठते ही चार अहम् फैसले किए हैं और यह चारों समाज के सर्वहारा वर्ग से जुड़े आम आदमी के कल्याण के हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक नया स्टार्टअप फंड भी बना दिया है। जो फैसले लिए गए हैं वह युवा, महिलाओं और कमजोर वर्ग के हितों से जुड़े फैसले हैं। अब नये अत्याधुनिक भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और केबिनेट सचिवालय एक जगह आ गये हैं। मोदी ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही चार फैसलों की जिस फाइल पर दस्तखत किए हैं वे युवाओं, महिलाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए हैं और ये फैसले सेवातीर्थ व कर्तव्य भवन से 140 करोड़ देषवासियों की सोच को बढ़ाने वाले साबित होंगे। मोदी ने जो चार अहम् फैसले किए हैं उनमें जीवन रक्षक पीएम राहत योजना शामिल है जिसके तहत हर पीड़ित को डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। इसका उद्देश्य यह है कि तत्काल इलाज न मिलने से किसी की जान न जाने पाये। इसका मतलब है कि पैसा जमा कराने की बाध्यता घटेगी और जान बच जायेगी। लखपति दीदी की संख्या मार्च 2029 तक 6 करोड़ करने का लक्ष्य है, 3 करोड़ का लक्ष्य मार्च 2027 से पहले पूरा करने का है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की सालाना आय एक लाख या उससे अधिक हो तो उसे लखपति दीदी माना जाता है और इससे ग्रामीण महिलाओं की आय को बढ़ाना ही मुख्य लक्ष्य है। किसानों की भी सुध ली गई है और कृषि कोष बढ़ाकर कृषि अधोसंरचना कोष का लक्ष्य एक से बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये किया गया है जिससे कि हमारे कृषि प्रधानदेश भारत में कृषि मूल्य श्रंखला मजबूत होगी। दूसरे षब्दों में कहा

जा सकता है कि सहकारी समितियों व कृषि उद्यमियों को कृषि ढांचे के लिए कर्ज और सहायता और गारंटी मिलती है जिससे अधिक से अधिक किसान इसका फायदा उठा सकेंगे। नवाचार तंत्र की मजबूती के लिए दस हजार करोड़ का फंड आफ फंड्स बनाया गया है। इससे प्रारंभिक चरण में स्टार्टअप और डीप रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इससे पूर्व 2016 में दस हजार करोड़ का फंड आफ फंड्स बनाया गया था।

अस्थायी परमिट शुल्क बढ़ाती राज्य सरकार

मध्यप्रदेश सरकार ने शहर में चलने वाले नगर वाहनों और मालवाहक वाहनों पर लगने वाले परिमट एवं टेक्स में अहम् बदलाव किये हैं। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मोटर कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए अब शहरी मार्ग की जगह नगरीय मार्ग की नई परिभाषा लागू की है जिसका सीधा-सीधा असर उन सिटी बसों पर पड़ेगा जो नगर निगम सीमा से बाहर तक के नोटीफाइड रुट पर चलती हैं। इन बसों से अब 150 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही यानी 50 रुपये महीना कर वसूला जायेगा। सरकार का मानना है कि इस संशोधन का उद्देश्य कर प्रणाली को और अधिक सुस्पष्ट और उपयोगिता आधारित बनाना है। अब टेक्स तय अवधि की बजाए वाहन द्वारा तय की गयी दूरी के आधार पर लिया जायेगा। संबंधित तकनीकी संशोधन एनआईसी पोर्टल पर लागू किए जायेंगे। जो बदलाव हुए हैं उसके अनुसार अधिसूचित नगरीय मार्गों पर 50 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह टेक्स लिया जायेगा। पहले अवधि तय नहीं थी अब अवधि तय कर दी गयी है। अस्थायी परमिट शुल्क 12 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 18 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। पहले मालवाहक वाहन से लाइफ टाइम टेक्स पूरी बॉडी बनने के बाद कुल कीमत पर लगता था अब यदि चेसिस अलग से खरीदी जाती है तो केवल चेसिस की कीमत पर ही टेक्स लगेगा।

और यह भी

भोपाल की श्यामला हिल्स पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के मुक्त- आकाश प्रदर्शनीय परिसर में जनजातीय आवास में भारत की जीवित जनजातीय परम्पराओं के संरक्षण की एक नई शुरुआत हो गयी है। इस साल में अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति और नागालैंड की कोन्याक नागा जनजाति के पारंपरिक कारीगर और समुदाय प्रतिनिधि भोपाल पहुंच कर अपने-अपने पारंपरिक आवासों के पुनरुद्धार कार्य में जुट गए हैं। यह कार्य पारंपरिक तकनीकों, स्थानीय सामग्रियों और सामुदायिक ज्ञान के आधार पर किया जा रहा है ताकि इन संरचनाओं की मौलिकता और सांस्कृतिक प्रामाणिकता बनी रहे। जनजातीय आवास मुक्त प्रदर्शनी के प्रभारी अधिकारी श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि वेस्ट सियांग;अरुणाचल प्रदेषद्ध के गाला समुदाय को तानी समूह के पूर्वज आबोतानी का वंशज माना जाता है। उनका आवास लकड़ी और बांस के खम्भों पर ऊंचाई में निर्मित विशाल आयताकार संरचना का होता है जिसकी छत ताड़ के पत्तों और स्थानीय वन संसाधनों से बनाई जाती है। आवास के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक प्रवेश द्वार, केंद्रीय अग्नि स्थल और परिवार प्रमुख के पीछे स्थित पवित्र स्थान गालो समाज की धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। इसी तरह नागालैंड के कोन्याक नागा समुदाय का ''मोरुंग'' यानी युवागृह सह ग्राम द्वार भी संग्रहालय परिसर में पुर्नस्थापित किया जा रहा है। संग्रहालय के निदेशक प्रो. डॉ. अमिताभ पांडे के अनुसार यह पहल केवल संरचनाओं के संरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि समुदाय की भागीदारी से जीवित परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

राज्य निर्वाचन आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में उलेखनीय कार्यों के लिए जिला क्लेक्टर्स को सम्मानित किया गया।

पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से मिले योजनाओं का लाभ : मंत्री श्री चौहान

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई आयोजित

भोपाल (नप्र)। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाए और छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं फील्ड स्तर पर सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री चौहान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक ले रहे थे। बैठक में समिति के सदस्य जतारा विधायक श्री हरिशंकर खटीक, पानसेमल विधायक श्री श्याम बरडे, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण श्री ई. रमेश कुमार और आयुक्त श्री सौरभ के. सुमन सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।विधायकगण द्वारा जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए।बैठक में अनुसूचित जाति बस्ती विकास,भवन विहीन छात्रावासों के निर्माण, छात्रावासों के रख-रखाव एवं अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति, प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाएँ और सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

एमसीयू में गौशाला की मांग को लेकर उपवास, छात्र बेहोश

प्रशासन ने दिया आश्वासन, विधायक आतिफ अकील बोले- एक गाय मेरी ओर से दान

भोपाल (नप्र)। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसी) में सोमवार को गौशाला निर्माण की मांग को लेकर छात्रों ने उपवास रखा। तेज धूप में भूखे-प्यासे बैठे रहने के कारण कुछ छात्रों को कमजोरी महसूस होने लगी। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और एक छात्र बेहोश हो गया। उसे तुरंत मेडिकल केयर उपलब्ध कराई गई।

छात्रों का कहना है कि यह मांग केवल आस्था से नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों से जुड़ी है। वहीं, भोपाल उत्तर विधायक आतिफ अकील ने वीडियो कॉल के जरिए समर्थन देते हुए एक गाय दान करने की घोषणा की, जिससे यह मुद्दिम राजनीतिक चर्चा में भी आ गई।

परिसर में उपवास, संवेदनशीलता की बात- एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण उपवास कर प्रशासन से गौशाला निर्माण की मांग की। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में सामाजिक सरोकारों और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे

कदम जरूरी हैं। कार्यकर्ताओं ने इसे जनहितकारी और मानवीय पहल है। भोपाल उत्तर विधायक आतिफ अकील ने वीडियो कॉल के जरिए समर्थन देते हुए एक गाय दान करने की घोषणा की।

उपवास के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

दोपहर लगभग 3 बजे उपवास का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई प्रदेश सचिव अमन पठान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद साथियों ने उन्हें तुरंत विश्वविद्यालय स्थित धन्वंतरी चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई। घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर चिंता का माहौल बन गया, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई।

प्रशासन ने दिया गौशाला के लिए आश्वासन

घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉ. शशिकला स्वयं मौके पर पहुंचीं। उन्होंने उपवास पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने गौ-शाला निर्माण की मांग पर प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता के साथ चर्चा कर सकारात्मक समाधान निकालने का आश्वासन दिया।

उज्जैन संभाग में भी दिखेगा नए सिस्टम का असर

एमपी में 18-19 फरवरी को बारिश के आसार, भोपाल-इंदौर में बादल छाएंगे

भोपाल (नप्र)। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से ग्वालियर, चंबल-सागर के साथ उज्जैन संभाग में भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 18 और 19 फरवरी को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और नीमच में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। भोपाल और इंदौर में बादल छा सकते हैं।

प्रदेश में मौसम का मिला-जुला असर दिखने को मिला। खंडवा-खरगोन में दिन का तापमान 34 डिग्री के पार पहुंच गया, तो दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रायसेन, रतलाम, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, सतना और उमरिया में पारा 30 डिग्री या इससे अधिक रहा।

वहीं, शनिवार-रविवार की रात की बात करें तो कटनी का करौंदी सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया। पचमढ़ी में 9.2 डिग्री, कल्याणपुर में 9.4 डिग्री और रीवा में 9.6 डिग्री रहा। 5 बड़े शहरों में इंदौर में सबसे कम 11.5 डिग्री, ग्वालियर में 11.7 डिग्री, भोपाल में 13 डिग्री, उज्जैन में 13.5 डिग्री और जबलपुर में तापमान 14.3 डिग्री दर्ज किया गया।

फरवरी में तीसरी बार भीगेगा एमपी

फरवरी के शुरुआत में ही प्रदेश में दो बार ओले, बारिश और आंधी का दौर रह चुका है। इससे फसलों को खासा नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने प्रभावित फसलों का सर्वे भी कराया था। इसके बाद अब तीसरी बार फरवरी भीगेगा।

डॉ. हेमलता का निधन, 60 करोड़ की संपत्ति अब किसकी ?

पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार; फर्जी दान-पत्र मामले में चल रही जांच

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमलता श्रीवास्तव का रविवार शाम को निधन हो गया। इसके साथ ही उनकी करोड़ों की संपत्ति को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं।

पोस्टमॉर्टम के बाद डॉक्टरों की टीम ने उनकी छोटी बहन शांति मिश्रा को शव सौंप दिया। अंतिम यात्रा राइट टाउन स्थित निवास से रानीताल मुक्तिधाम से निकाली गई। गौरीघाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। डॉ. हेमलता की बहन और गायत्री परिवार के एक सदस्य ने उन्हें मुखाग्नि दी।

डॉ. श्रीवास्तव की संपत्ति पर जांच जारी- तहसीलदार संदीप जायसवाल ने बताया कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसलिए डॉक्टर के घर में पुलिस बल तैनात किया गया है।

डॉ. श्रीवास्तव की संपत्ति के वारिस को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच एसडीएम स्तर पर की जा रही है। प्रशासन

डॉ. हेमलता श्रीवास्तव

तथ्यों के आधार पर निर्णय करेगा।

बता दें कि राइट टाउन निवासी डॉ. श्रीवास्तव को करीब एक माह पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ था, लेकिन रविवार को अचानक उनका निधन हो गया। उनके पति और बेटे का पहले ही देहांत हो चुका था। संपत्ति हड़पने के आरोप में डॉ. सुमित जैन, पत्नी प्राची जैन, उनकी बहन व जीजा पर मामला दर्ज है।

खंडवा में किन्नर गुरु वाहिद अहमद ने की घर वापसी, सनातन धर्म अपनाकर बनीं सीता

खंडवा (नप्र)। शहर की किन्नर गुरु वाहिद अहमद उर्फ 'सितारा गुरु' ने सनातन धर्म में घर वापसी करते हुए नया नाम 'सीता' धारण किया। यह धार्मिक अनुष्ठान महादेवगढ़ मंदिर में संपन्न हुआ, जहां वैदिक रीति-रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच यह प्रक्रिया पूरी कराई गई। किन्नर समाज ने ढोल ताशे के साथ गुरु का सम्मान किया।

महामंडलेश्वर के नेतृत्व में हुआ अनुष्ठान- वहीं, घर वापसी कार्यक्रम महामंडलेश्वर सखी सौम्या देवी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में विद्वान पंडितों की उपस्थिति में गंगाजल और गोमूत्र से शुद्धिकरण स्नान कराया गया। इसके बाद हवन-पूजन और विशेष आरती का आयोजन किया गया। ढोल-ताशों की गूंज के बीच उपस्थित श्रद्धालुओं और किन्नर समाज के लोगों ने 'सीता' का स्वागत किया। मंदिर के प्रबंधक अशोक पालीवाल ने बताया कि किन्नर समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व में उनसे मुलाकात कर इस संबंध में चर्चा की थी। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने वैदिक परंपराओं के अनुसार विधिवत कार्यक्रम आयोजित किया।

सनातन में जोड़ने की परंपरा से प्रभावित होकर बनीं सीता- धर्म परिवर्तन के बाद सीता ने कहा कि सनातन धर्म में हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है। उनका विश्वास पहले से ही सनातन में था लेकिन अब उन्होंने औपचारिक रूप से खुद को महादेव की शरण में समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जोड़ने की परंपरा का प्रतीक है। मैं चाहती हूं कि जीवन की शेष उम्र सनातन धर्म और समाज सेवा में बीते। सीता के रूप में समाज के हर तबके की सेवा कर आत्मिक शांति और सुख का अनुभव करना चाहती हूं।

महाशिवरात्रि पर लिया था संकल्प- सीता ने बताया कि उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन ही यह संकल्प लिया था कि अब वे महादेव की शरण में ही जीवन व्यतीत करेंगी। उसी निर्णय के तहत उन्होंने अपने किन्नर चेलों के साथ मंदिर पहुंचकर विधिवत घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की। कार्यक्रम के दौरान बाबा महादेव की विशेष आरती किन्नर समाज द्वारा की गई। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला।

संपादकीय

रेरा के औचित्य पर सवाल

देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अपने मूल उद्देश्य से भटक कर केवल डिफाल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। रेरा के बारे में देश की सर्वोच्च अदालत की यह राय न केवल महत्वपूर्ण बल्कि जमीनी हकीकत के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट की इस राय को मप्र की रेरा की हालत से और बल मिलता है, जो डिफाल्टर बिल्डरों से राशि तक वसूल नहीं कर पा रही है। ऐसे में यदि मकान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है तो रेरा को बनाए रखने पर करोड़ों खर्च करने के क्या मायने है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद कमाई का जरिया बन गई हो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें रेरा के गठन पर दोबारा विचार करें। यह संस्था खरीदारों की मदद के बजाय केवल डिफॉल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है। कोर्ट ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए रेरा बनाया गया था, वह पूरी तरह भटक गया है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि रेरा में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, तो चीफ जस्टिस ने कहा- हर राज्य में यह रिटायर्ड नौकरशाहों के लिए एक 'रिहैबिलिटेशन सेंटर' बन गया है। चीफ जस्टिस ने कहा- जिन लोगों यानी होमबायर्स के लिए यह संस्था बनाई गई थी, वे आज पूरी तरह निराश और दुखी हैं। उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। पूरा मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के उस नोटिफिकेशन से जुड़ा था, जिसमें रेरा ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की बात कही गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑफिस शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि होमबायर्स की सुविधा के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल को भी धर्मशाला शिफ्ट किया जाए। सितंबर 2024 में भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा था कि रेरा पूर्व नौकरशाहों का ठिकाना बन गया है, जिन्होंने इस एक्ट की पूरी भावना और योजना को ही विफल कर दिया है। होमबायर्स की संस्था 'फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स' (एफपीसीई) ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कहा- रेरा कानून को आए 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रेरा-रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर रेरा खरीदारों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता, तो इसमें बड़े सुधार की जरूरत है या फिर इसके अस्तित्व पर ही दोबारा विचार होना चाहिए। गौरतलब है कि रेरा की स्थापना 2016 में की गई थी। इस सरकारी संस्था का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना, बिल्डरों की जवाबदेही तय करना और खरीदारों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन वास्तव में वैसा कुछ नहीं हो रहा। मप्र में सैंकड़ो प्रोजेक्ट रेरा की मंजूरी न मिलने के कारण अटके पड़े हैं। पिछले आठ वर्षों में मप्र रेरा ने बिल्डरों के खिलाफ 2382 मामलों में 374 करोड़ रु. की राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए। हालांकि इनमें से केवल 10 करोड़ रुपए (2.62%) की ही वसूली हो सकी है। मप्र में हर महीने ग्राहकों की क्षतिपूर्ति, मूलभूत सुविधाओं की कमी और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से जुड़े 200 से 250 मामले रेरा में दर्ज होते हैं।

पृथक बुंदेलखंड : उपेक्षा, अस्मिता और विकास की अधूरी कहानी

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला बुंदेलखंड लंबे समय से सूखा, पलायन, बेरोजगारी और विकास की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग समय-समय पर उठती रही, जिसे हाल के वर्षों में अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने राजा बुंदेला ने फिर प्रमुखता से सामने रख दिया। समर्थकों का तर्क है कि बड़े राज्यों की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में यह क्षेत्र हमेशा हाशिए पर रहा, इसलिए अलग राज्य बनने से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नीतियां बन सकेंगी। यह बहस केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता, संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और संतुलित विकास के मॉडल से जुड़ा व्यापक प्रश्न बन चुकी है।

नजरिया

हेमंत पाल

लेखक 'सुबह सवेरे' के स्थानीय संपादक हैं।

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में फैला बुंदेलखंड लंबे समय से उपेक्षा, सूखा, पलायन और विकास की कमी जैसे सवालों से जूझता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग समय-समय पर उठती रही है। हाल के वर्षों में फिल्म अभिनेता से सामाजिक कार्यकर्ता बने राजा बुंदेला इस मांग को मुखर रूप से उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जब तक बुंदेलखंड को प्रशासनिक रूप से अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक इस क्षेत्र की समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का मूल आधार क्षेत्रीय असमानता और ऐतिहासिक उपेक्षा का आरोप है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिलों के साथ मध्य प्रदेश के सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, दतिया जैसे जिलों में फैला है।

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह इलाका खनिज संपदा, पत्थर, ग्रेनाइट और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है, लेकिन मानव विकास सूचकांकों में लगातार पीछे रहा है। यहां औसत वर्षा कम और अनियमित है, जिससे बार-बार सूखे की स्थिति बनती है। खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है और सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। समर्थकों का तर्क है कि बड़े राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बुंदेलखंड हमेशा हाशिए पर रहा। लखनऊ या भोपाल से दूर स्थित यह इलाका राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नहीं माना जाता, इसलिए बजटीय आवंटन और योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित ध्यान नहीं मिला। वे उदाहरण देते हैं कि सूखा राहत पैकेज, सिंचाई परियोजनाएं और औद्योगिक निवेश घोषणाओं तक सीमित रह जाते हैं। अलग राज्य बनने पर स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति बना सकेगा और संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार होगा।

आर्थिक आधार के साथ-साथ सांस्कृतिक तर्क भी दिए जाते हैं। बुंदेलखंड की अपनी विशिष्ट बुंदेली बोली, लोकगीत, वीरगाथाएं और ऐतिहासिक परंपराएं हैं। ओरछा, खजुराहो, झांसी जैसे ऐतिहासिक केंद्र इसकी पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। अलग राज्य समर्थकों का कहना है कि क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित करने के लिए प्रशासनिक स्वायत्तता जरूरी है। वे यह भी तर्क देते हैं कि छोटे राज्यों के गठन के बाद विकास की गति तेज होने के उदाहरण सामने आए हैं, जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। हालांकि इन राज्यों के अनुभव पूरी तरह एक जैसे नहीं रहे, फिर भी समर्थक इन्हें सकारात्मक मिसाल के रूप में पेश करते हैं।

बुंदेलखंड राज्य की मांग नई नहीं है। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन के समय भी क्षेत्रीय पहचान के आधार पर चर्चा हुई थी, लेकिन बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला। 1950 और 60 के दशक में कुछ स्थानीय संगठनों ने आवाज उठाई, पर वह व्यापक जन आंदोलन का रूप नहीं ले सकी। 1990 के दशक में जब उत्तराखंड (तब

उत्तरांचल) के आंदोलन ने जोर पकड़ा, उसी समय बुंदेलखंड में भी अलग राज्य की मांग ने फिर सिर उठाया। 2000 में जब तीन नए राज्य बने, तब भी बुंदेलखंड समर्थकों ने उम्मीद जताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में यह मुद्दा फिर चर्चा में आया। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव पारित कराया था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, पर केंद्र सरकार ने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि राज्य पुनर्गठन केवल विधानसभा प्रस्ताव से संभव नहीं, बल्कि संसद की स्वीकृति और व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी है।

राजनीतिक दलों का रुख भी समय-समय पर बदलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने अलग-अलग समय पर छोटे राज्यों के सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन बुंदेलखंड के सवाल पर कोई ठोस पहल नहीं की। क्षेत्रीय दलों ने भी इसे चुनावी मुद्दा तो बनाया, पर सत्ता में आने के बाद प्राथमिकता सूची में यह पीछे चला गया। इसी पृष्ठभूमि में राजा बुंदेला का नाम उभरा। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 'बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा' जैसे मंचों के माध्यम से अलग राज्य की मांग को संगठित रूप देने का प्रयास किया। उनका दावा है कि बुंदेलखंड की जनता लंबे समय से शोषण और उपेक्षा झेल रही है, और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में समस्याएं जस की तस हैं। वे धरना-प्रदर्शन, पदयात्रा और जनसभाओं के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श में लाने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक उनके साथ लोगों की संख्या का प्रश्न है, इसका सटीक आंकड़ों में मापन कठिन है। कोई आधिकारिक जनगणना या सदस्यता रजिस्टर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जिससे यह बताया जा सके कि कितने लोग सक्रिय रूप से आंदोलन से जुड़े हैं। हालांकि, बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में उनके समर्थक संगठन मौजूद हैं और समय-समय पर सैकड़ों-हजारों लोगों की रैलियां आयोजित की जाती रही हैं। यह भी सच है कि यह आंदोलन अभी तक उत्तराखंड आंदोलन जैसी व्यापक जनलहर का रूप नहीं ले सका है। जनसमर्थन क्षेत्र विशेष में केंद्रित है और इसे सर्वदलीय या सर्व समाज समर्थन नहीं मिला है। आंदोलन की एक चुनौती यह भी है कि बुंदेलखंड दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है। यदि अलग राज्य बनाना हो तो दोनों राज्यों के हिस्सों को मिलाकर नया राज्य बनाना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों विधानसभाओं और केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक होगी। यह संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा, कुछ लोग तर्क देते हैं कि नया राज्य बनने से प्रशासनिक खर्च बढ़ेगा और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

विरोधियों का कहना है कि समस्या राज्य के आकार में नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता में है। यदि सिंचाई, जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीरता से काम हो तो बिना राज्य विभाजन के भी विकास संभव है। वे उदाहरण देते हैं कि विशेष पैकेज, जैसे बुंदेलखंड पैकेज, पहले भी दिए गए हैं। हालांकि समर्थक यह सवाल उठाते हैं कि इन पैकेजों का पूरा लाभ जमीन पर क्यों नहीं दिखा। बुंदेलखंड के अलग राज्य की मांग भावनात्मक, आर्थिक और प्रशासनिक तर्कों का मिश्रण है। यह केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असंतोष की अभिव्यक्ति भी है। फिर भी, किसी भी नए राज्य के गठन के लिए व्यापक जनमत, राजनीतिक सहमति और आर्थिक व्यवहार्यता का स्पष्ट खाका जरूरी होता है। अभी तक यह आंदोलन प्रतीकात्मक और क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक समर्थन हासिल नहीं कर पाया है।

राजा बुंदेला और उनके समर्थकों की सक्रियता ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। वे इसे केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न बताते हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह आंदोलन व्यापक जनसमर्थन जुटा पाता है और क्या राष्ट्रीय राजनीति में इसे वह स्थान मिल पाता है, जो कभी उत्तराखंड या झारखंड आंदोलनों को मिला था। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि बुंदेलखंड का प्रश्न केवल अलग राज्य के गठन तक सीमित नहीं है; यह उस व्यापक बहस का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्रीय असमानता, विकास का मॉडल और शासन की जवाबदेही जैसे मूल प्रश्न शामिल हैं।

भ्रामक समय में स्पष्ट हो संदेश

मुद्दा

डॉ. गरिमा संजय दुबे

लेखक साहित्यकार हैं।

इन दिनों जिस तरह दुनिया में उथल पुथल मची है, और समाचारों की बाढ़ ने जिस तरह हर मन मस्तिष्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया है उससे यह संकट उत्पन्न हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत । भ्रम में केवल भारत, भारत की जनता या भारत का सरकार या विपक्ष ही नहीं है बल्कि या स्थिति विश्व के हर देश में है । पिछले दिनों विदेश में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से चर्चा में यह बात और स्पष्ट हुई ।

भारत के संदर्भ में यह बात और चिंताजनक इसलिए हो जाती है कि हम आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक पाखंडी समाज में रहते हैं । जितना सुंदर हमारा साहित्य, धर्म, संस्कृति, कला है उतने ही अधिक विकार की संभावना सदा रही है । मुझे कहने दीजिए कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत के अतिरिक्त सबके हित की सोचता है, वह अपने हित की सोचता है, राष्ट्र उसके लिए दूसरे या तीसरे स्थान पर आता है, बहुत थोड़े हैं जो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर राष्ट्र प्रथम की भावना को स्थान देते हैं ।

दूसरे देशों में इतनी विसंगतियां नहीं है फिर भी वे युद्धरत हैं और पीड़ित हैं, भारत में अनेक विसंगतियां हैं फिर भी वह तुलनात्मक रूप से स्थिर है, शांत है, यह एक चमत्कार ही है । कहना चाहती हूं कि यदि हम स्वयं समस्या खड़ी न करें और राष्ट्र हित को, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, दल की क्षुद्र राजनीति और विचारधारा से ऊपर उठकर सोच सकें तो कोई भारत के आगे नहीं टिकता, किंतु यह होता नहीं दिखाई देता, अनेकता में एकता का नारा अब विभाजित होता दिखाई दे रहा है, और इसलिए आदर्शों में, मूल्यों में, नैतिकता में, अध्यात्म में लिखित रूप से बहुत आकर्षक दिखाई देने वाला समाज व्यावहारिकता में उतने ही खंडों में विभाजित रहा है ।

सूचनाओं के अंबार ने, हर किसी को कहीं भी कुछ भी बोल देने की, अपने मन अनुसार कंटेंट बना लेने की सुविधा ने जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा थमा दिया है । बने हुए कंटेंट, वीडियो क्लिप्स, AI से बनाए गए वक्तव्य, अपने अपने लाभ के लिए समाचार बना रहे हैं । सच जाने बिना ही सनसनी फैलाने और भ्रमित करने के प्रपंच अनियंत्रित गति से बढ़ रहे हैं, झूठी बातों के प्रचार पर कोई नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रहित से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को सार्वजनिक करने पर कोई दंड नहीं है । नीतियों में पारदर्शिता नहीं है, और जनता तक नीतियों के सही स्वरूप को पहुंचाने की ईमानदार कोशिश नहीं दिखाई दे रही । जानबूझ कर आधी अधूरी जानकारियां प्रदान कर जनमानस को भ्रमित किया जा रहा है ।

सरकार हो या विपक्ष, उनके प्रवक्ताओं को गंभीरता से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का उपक्रम करना चाहिए न की सनसनी फैलाने जैसे टूल्स का सहारा लेकर, शोर करके, अराजकता के साथ, जिद और अहंकार के साथ भ्रम को और बढ़ाना चाहिए ।

पक्ष विपक्ष सदा रहते आएं हैं ,सदा ही रहेंगे, यह तो शाश्वत है, किंतु मर्यादा, गरिमा, संयम, शांत ढंग से कही हुई बात का प्रभाव अधिक होता है ।अब तो ऐसा लगता है जैसे शांति से, संयम से बात सुने न जाने कितने युग बीत गए । हर कोई चिल्लाकर, शोर करके, आक्रामक मुद्रा में, अपनी बात कह कर मुद्दों को भ्रमित कर रहा है । सरकार ने राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए हैं उसको प्रभावी तर्क से वह जनमानस के सामने रखे, विपक्ष सरकार से प्रश्न करने का अधिकारी सदा रहा है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किंतु हर बात में अविश्वास करके वह किस राष्ट्रहित की बात करता है यह स्पष्ट करे । लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के निर्णयों पर भरोसा न करके क्या राष्ट्र को विपक्ष के अराजक, निराधार, संदेहास्पद अविश्वास योग्य वक्तव्यों पर भरोसा करना चाहिए ? क्यों केवल इसलिए कि आपको लोकतंत्र ने विरोध का अधिकार दिया है, तो यह स्तर होगा विरोध का। विपक्ष को अपनी नकारात्मक राजनीति के नुकसान पता होने चाहिए। हर बार आरोप लगाकर भाग जाने की प्रवृत्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता, हास्यास्पद ढंग से अपनी अराजकता को अपनी बुद्धिमानी समझने का अहंकार भी बहुत स्पष्ट दिखाई देता है । प्रश्न पूछने वाले में उत्तर सुनने और समझने का धैर्य भी होना चाहिए। सरकार उत्तर दे जनता सुनेगी, क्योंकि सरकार विपक्ष के प्रति नहीं राष्ट्र और जनता के प्रति उत्तरदाई है ।

पिछले बारह वर्षों में किसी भी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया । ऐसा कभी, कहीं नहीं हुआ । क्या पिछले बारह वर्षों में सरकार का एक भी निर्णय ऐसा नहीं जो देश हित में है, जिस पर बिना दलगत राजनीति किए जनमत का सम्मान करते हुए विपक्ष ने सरकार का साथ दिया हो, याद कीजिए, नहीं हुआ, सरकार के किसी फैसले पर विपक्ष का कोई सहयोग नहीं मिला । तमाम विरोध के बाद हर कहीं, हर देश में कुछ मुद्दों पर पक्ष विपक्ष एकजुट होकर राष्ट्रहित में काम करते हैं, भारत में भी इसके पूर्व यह उदाहरण बनते रहे हैं, राष्ट्रहित में पक्ष विपक्ष एक रहे ताकि किसी को हमें कमज़ोर करने का मौका न मिले, किंतु अब भारत में वयम पंचाधिकम शतम, का भाव नदारद है । बहुधा संदेश यह जाता है कि भारत विरोधी स्वर का सहयोगी है विपक्ष ।

सरकार की तरफ से यह प्रयास अनेक बार हुए जब विपक्ष का सहयोग मांगा गया किंतु सहयोग नहीं मिला । जनता देखती है, समझती है, तमाम भ्रम के बाद भी यह तो उसकी समझ में आता है कि शोर सच नहीं होता, अराजकता आश्वस्त नहीं कर सकती, हल्ला करके हल नहीं निकलता । विपक्ष के सरकार से असहयोग का यह रवैया एक व्यक्ति और दल के विरोध से बढ़ते-बढ़ते राष्ट्र विरोध,संस्कृति विरोध तक जा पहुंचा है । सत्ता से दूरी ने विपक्ष को निराश और कुंठित किया है और उसकी अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ।

सरकार भी अपने संयम में यह न भूले कि जनता तक मुद्दों को स्पष्ट तरीके से पहुंचाने का काम उनका है, जनता से संवाद को और अधिक मजबूत बनाइए, केवल ढूञ्ज सेल के कंटेंट से नहीं अपने प्रतिनिधियों को सही जानकारी देने के लिए बाध्य कीजिए । शोर को शोर से नहीं तर्कों से पराजित कीजिए, अराजकता को आक्रामकता से नहीं अनुशासन से नियंत्रित कीजिए, और हल्ले को हितकारी संवाद और उसके प्रचार से समाप्त कीजिए ।

हां यह देखा गया है कि बार बार स्पष्टीकरण के पश्चात भी विपक्ष का अविश्वास राग समाप्त नहीं होता और वह हर निर्णय में विघ्नसंतोषी की तरह व्यवहार करता है, किंतु सरकार जनता के प्रति इसे प्रथम दायित्व समझ कर करे, अंततः जनता ही लोकतंत्र की रीढ़ है । उसके बाद भी हठी, अहंकारी, अराजक विपक्ष न माने तो उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, जनता तय कर लेगी । सरकार की तरफ से मुद्दों पर फैले भ्रम को दूर करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यह सरकार का दायित्व भी है और समय की मांग भी ।

ममलेश्वर नहीं, अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग

संदर्भ

श्रीकृष्ण 'जुगनू'

लेखक वरिष्ठ शिक्षाविद और ज्ञान-शोध विशेषज्ञ हैं।

द्वादश ज्योतिर्लिंग' मध्यकालीन शिवपुराण की अद्भुत मान्यता है। देशभर, विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा और आबू (कुछ हिमालय, नेपाल) जैसे शिव तीर्थों और शिव संबंधी कथाओं का सर्वेक्षण करके शिव संन्यासियों ने कामिकागम, शिवधर्म और शिवधर्मोत्तर के साथ नंदीकेश्वर पुराण का पुनर्गठन किया और कुछ स्रोत, रुद्राक्ष महिमा, स्वरोदय, मृत्युकारक निमित्त और अन्य लक्षणों को भी महत्व दिया। इस पुराण में ज्योतिर्लिंग की मान्यता देश की एकात्मकता और शिव सन्धि की सुंदर अवधारणा है।

हालांकि प्राचीन शिव पुराणों (वायु, कूर्म, वामन, मत्स्य और शिवधर्म, शिव धर्मोत्तर जैसे उपपुराण) में ज्योतिर्लिंग का विवरण नहीं मिलता। कूर्मपुराण के दूसरे खंड (ऊपरी भाग) में नर्मदा नीमाड़ क्षेत्र के तीर्थों के रूप में नर्मदा के तटवर्ती अंगारेश्वर, विमलेश्वर, शूलभेद, बलि तीर्थ, ऋषि तीर्थ, महेश्वर, अहल्या आदि कई तीर्थों की महिमा आई है। (कूर्मपुराण उपरि विभाग अध्याय 39) यह विवरण हालांकि कूर्म जैसे वैष्णव पुराण के शैव स्वरूप में आगमन के समय का है लेकिन वहां पर 'ध्वज' नामांत वाले यति तथा पाशुपत मत के प्रसार की सूचना लिए है। संयोगवश मांधाता क्षेत्र में तब तक 'अमरेश्वर मंदिर' की ख्याति बढ़ चुकी थी। यह वही शिवालय है, जिसे आजकल त्रुटिपूर्ण रूप से 'ममलेश्वर' कहा जाता है। इस मंदिर में परमार कालीन संवत् 1120 (1063 ई.) का अभिलेख है और उसमें एक बार नहीं, 4 - 5 बार अमरेश्वर नाम उत्कीर्ण किया गया है।

उस समय यहां शिव भट्टारक गंधध्वज प्रभावी थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से शिव की स्तुति के रूप में 'शिव महिम्न' को अमरेश्वर के सम्मुख लिखा। शिव महिम्न का यह प्राचीनतम उत्कीर्ण रूप है जिसमें आज प्रचलित पाठ से कुछ श्लोक कम है। इस शिलालेख में उत्कीर्ण है:

श्री अमरेश्वर देवाग्रतः शिवभक्त भट्टारक गंधध्वजः परमभक्तया स्तुतिरियं स्वयमालिखत्। संवत् 1120 मंगलं महाश्री। इति शुभम। यम - नियम - स्वाध्यायभिरत जगतविख्यातं कीर्ति ... अमरेश्वर देवं पादाब्जं नित्यं प्रणमति।

और देखिए, राशि नामांत वाले पाशुपत पंडित संन्यासी ज्ञानराशि भी यहां के भट्टारक हुए। उनका लेखन है:

भट्टारकं सुशील पण्डित ज्ञानराशि परम भक्तयां निःशेष सुरासुराधिप श्री अमरेश्वरं देवपादान् सदा नित्य प्रणमति...।

और भी नाम सहित लिखा है: श्री अमरदेवं भक्तयां नित्य प्रणमति।

मुझे याद आता है कि भट्ट लक्ष्मीधर के कृत्य कल्पतरु महाग्रंथ के तीर्थ विवेचन कांड में अवंतिपुरी के महाकाल तीर्थ के बाद जिस तीर्थ का उल्लेख मिलता है, वह अमरेश्वर है, वहां ओंकारेश्वर का उल्लेख नहीं है। यथाः तत्राह्यमरेश्वरमं देवं दृष्ट्वा सम्पूज्य भक्तितः। (पृष्ठ 236)

गीताप्रेस के 'शिवपुराण' के संवत् 2075 के संस्करण में द्वादश ज्योतिर्लिंग वाले श्लोक के अमरेश्वर का नाम ही नहीं है, बल्कि ओंकारेश्वर में 'परमेश्वर' का नाम दे दिया गया है:

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम।
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम्।।
(कोटिरुद्र संहिता)

मंदिर के शिलालेख में ये अक्षर और उनका पाठ पहचानना आसान नहीं है। आजकल तो इतनी भीड़ हो गई है कि दर्शन हो जाए तो भी भाग्य समझना चाहिए। मैं सोच में पड़ा हुआ हूं कि तीर्थों का ज्ञानपीठ होना कहाँ खो गया? किसी को अभिलेख की नहीं पड़ी। भीड़ में पीठ लगने से कहीं घिस न जाए, तो अभिलेखों वाली भित्तियाँ काँच से मंडित कर दी गई हैं। मैंने रामेश्वर गौरीशंकर ओझा द्वारा 1933 में लिखित एक आलेख में इस अमरेश्वर शिवालय का विवरण पढ़ा है तो मन था कि उस अभिलेख का पता लगाना चाहिए। पिछले दिनों भगवान अमरेश्वर के दर्शन के साथ ही महिम्न अभिलेख के दर्शन भी हो गए। इसकी लिपि वही है जो धारानगरी की भोजशाला और उदयपुर मालवा के नीलकंठ महादेव मंदिर के 1137 ई. के उत्कीर्ण अभिलेखों में है...।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

वाई-फाई का खूँटा और डेटा का उपवास

प्रौबतगंज की पंचायत में इन दिनों एक नया 'फर्मा' (साँचा) आया है–डिजिटल इंडिया। हमारे प्रधान जी ने तय किया है कि अब गाँव की समस्याएँ भगवान भरोसे नहीं, बल्कि 'सर्वर' भरोसे सुलझेंगी। उन्होंने एक ऐसा 'डिजिटल ढाँचा' तैयार किया है जिसमें हर आदमी एक 'यूजर आईडी' है और उसकी भूख एक 'एरर'।

पंचायत भवन के चबूतरे पर एक नया 'वाई-फाई' का खूँटा गड़ा है। गाँव के बुजुर्ग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई परग्रही जीव उनके आंगन में आकर खड़ा हो गया हो। प्रधान जी हाथ में एक चमचमाता टैबलेट लेकर ऐसे घूमते हैं जैसे कालिदास ने मेघदूत नहीं, बल्कि 'ब्रॉडबैंड-दूत' लिखा हो। उन्होंने गाँव वालों से कहा, 'अब अंगूठा लगाना छोड़ो, अब तुम सब 'लॉग-इन' हो गए हो!'

पर दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ विकास का 'मार्क्सवादी साँचा' अभी भी ज़िंदा है। सचिव साहब के पास एक ही गणित है–जब तक किसी कागज़ पर किसी गरीब की 'अस्मत' और किसी अफसर की 'रिश्वत' का मिलन न हो, तब तक विकास की फाइल आगे नहीं बढ़ती। वे डिजिटल होने के नाम पर लैपटॉप तो ले आए हैं, पर उस पर काम करने के बजाय वे उस पर लूडो खेलते हैं और कहते हैं, 'यह डेटा-माइनिंग की प्रक्रिया है।'

एक दूसरे प्रकार के 'फ्रॉयडवादी' अफसर आए हैं। उनकी दृष्टि में गाँव का किसान केवल 'वोट' है और उसकी समस्याएँ केवल 'ग्रंथियाँ'। वे गाँव में नाली बनवाने के बजाय 'मानसिक स्वास्थ्य' का कैंप लगवाते हैं। वे कहते हैं, 'तुम्हारी नाली जाम नहीं है, तुम्हारा अवचेतन मन कुंठित है।' किसान बेचारा अपना फटा कुर्ता देखता है और सोचता है कि ये साहब कौन से 'कोकशास्त्र' का ज्ञान बाँट रहे हैं।

आजकल गाँव में कुछ 'एनसाइक्लोपीडिया' टाइप के युवक भी आ गए हैं। वे न खेती जानते हैं, न खलिहान, पर उनके पास गूगल का ज्ञान है। वे गाँव के नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 'सतत विकास' पर ऐसा भाषण झाड़ते हैं कि खुद नीम का पेड़ भी सूखने लगता है। वे तर्क ऐसे देते हैं जैसे 'मेगाबाइट' में रोटी पकाई जा सकती हो।

असल में, विकास का यह 'साँचा' उस खाली डिब्बे जैसा है जिसके भीतर मिठाई कभी थी ही नहीं। प्रधान जी और सचिव साहब उस खाली डिब्बे को जनता को दिखाकर कहते हैं–'देखो, कितनी ताज़ा खुशबू है!' और जनता, जिसे न भूख का हिसाब पता है न हकीकत का, वह उस डिब्बे को चाटने में लगी है।

चरित्र रचने के लिए, या कहिए गाँव बनाने के लिए, उस कीचड़ में पैर डालना पड़ता है जहाँ मच्छरों का तांडव होता है। एसी (AC) कमरे में बैठकर 'स्मार्ट विलेज' की योजना बनाना वैसा ही है जैसे किसी कुंवारे को 'बाल-पालन' की पुस्तक थमा देना। हमारे नए योजनाकारों ने गाँव को केवल 'सेटअप' मान लिया है। वे ताजगी ढूँढने के लिए गाँव में 'पिकनिक' मनाने आते हैं, दो-चार सेल्फी लेते हैं, और शहर जाकर 'ग्रामीण विमर्श' पर लेख लिखते हैं।

सच तो यह है कि जब तक तपस्या की आंच नहीं लगेगी, तब तक न अच्छा उपन्यास बनेगा और न ही अच्छा गाँव। आप मेघदूत की बात करते हैं, यहाँ तो 'मेल-दूत' भी समय पर नहीं पहुँचता क्योंकि नेटवर्क गायब है। विकास केवल साँचों में नहीं आता, वह उस पसीने में आता है जिसे सचिव साहब अपनी मखमली रुमाल से पोंछकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं।

तकनीक

विशाल कुमार सिंह

जीनोम एडिटिंग की चुनौतियां

जीनोम एडिटिंग वह आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए किसी पौधे के डीएनए में बदलाव करके उसमें विशेष गुणों को जोड़ा या हटाया जाता है। परंपरागत जेनेटिक इंजीनियरिंग में बाहरी जीन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जीनोम एडिटिंग एक तरह की 'सर्जरी' है जो पौधे के अपने ही जीन में परिवर्तन करती है। भारत में पहली बार इस तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने दो नई चावल किस्में विकसित की हैं- DRR Dhan-100 और Improved Samba Mahsuri (ISM-1)। इन दोनों किस्मों की विशेषता यह है कि इन्हें कम पानी, कम खाद और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। यही नहीं, इनका उत्पादन सामान्य चावल की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है और पकने में भी ये किस्में लगभग 20 दिन पहले तैयार हो जाती हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में भारत ने एक बार फिर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। कृषि क्षेत्र में 'जीनोम एडिटिंग' के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों ने चावल की दो नई किस्में विकसित करके न केवल वैश्विक स्तर पर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन का द्वार भी खोल दिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'जेनेटिक मॉडिफिकेशन' से अलग है, और इसके सामाजिक तथा कानूनी प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम हैं।

जीनोम एडिटिंग वह आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए किसी पौधे के डीएनए में बदलाव करके उसमें विशेष गुणों को जोड़ा या हटाया जाता है। परंपरागत जेनेटिक इंजीनियरिंग में बाहरी जीन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि जीनोम एडिटिंग एक तरह की 'सर्जरी' है जो पौधे के अपने ही जीन में परिवर्तन करती है। भारत में पहली बार इस तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने दो नई चावल किस्में विकसित की हैं- DRR Dhan-100 और Improved Samba Mahsuri (ISM-1)। इन दोनों किस्मों की विशेषता यह है कि इन्हें कम पानी, कम खाद और कम कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। यही नहीं, इनका उत्पादन सामान्य चावल की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है और पकने में भी ये किस्में लगभग 20 दिन पहले तैयार हो जाती हैं।

इस तकनीक के माध्यम से एक ही प्लांट में मौजूद जींस को एडिट करके डीएनए सीक्वेंसिंग में परिवर्तन किया जाता है। इससे उत्पन्न पौधे को कोई बाहरी या कृत्रिम तत्व ग्रहण नहीं करना पड़ता, जिससे यह तकनीक जैविक और पारंपरिक कृषि के बीच की दूरी को भी पाट सकती है। DRR Dhan-100 और ISM-1 को 'जीनोम एडिटिंग' के माध्यम से तैयार किया गया है और इन्हें बिना किसी जैविक जोखिम के बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।

इस वैज्ञानिक उपलब्धि के पीछे सरकार की स्पष्ट रणनीति और दृष्टिकोण भी अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि मंत्री ने 'माइनस 5 प्लस 10' का नारा देते हुए कहा है कि पाँच मिलियन हेक्टेयर में कम क्षेत्रफल में दस मिलियन टन अतिरिक्त चावल उगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह संकल्प केवल खाद्यान्न उत्पादन की दिशा में नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और भूमि की घटती उर्वरता से निपटने की दिशा में भी बड़ा कदम है। किसानों को अल्प जल वाले क्षेत्रों में भी उच्च उपज देने वाली किस्मों की उपलब्धता कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।

भारत जैसे देश में जहां कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है और अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, वहाँ यह तकनीक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। जीनोम एडिटिंग की सहायता से तैयार की गई फसलों की उत्पादकता अधिक होती है और संसाधनों की खपत कम होती है, जिससे किसान की लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के संसाधनों की भारी कमी है या भूमि की उर्वरता लगातार घट रही है, वहाँ इस तकनीक से तैयार किस्में किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं।

इस तकनीक का एक अन्य प्रमुख पक्ष है 'क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन' यानी फसल विविधीकरण। सरकार चावल की अधिक खपत वाली खेती को दालों और तिलहनों की खेती की ओर मोड़ना चाहती है, जिससे जल संकट और पोषण असंतुलन से निपटा जा सके। पारंपरिक चावल की खेती में अधिक जल की आवश्यकता होती है और यह हरित क्रांति के समय से ही उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भूजल के अत्यधिक दोहन का कारण रही है। अब यदि कम जल-खपत वाली किस्में किसान को उपलब्ध कराई जाएंगी तो किसान को चावल की पैदावार कम किए बिना दाल और तिलहन की ओर बढ़ने की सुविधा मिलेगी।

वर्तमान में भारत में चावल, गेहूं जैसी खाद्यान्न फसलें अधिक उगाई जाती हैं जबकि दाल और तिलहन के मामले में हम अभी भी आयात पर निर्भर हैं। खाद्य तेल और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए यदि हम कृषि संरचना में संतुलन स्थापित कर पाएं तो यह पोषण सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों दृष्टियों से लाभकारी होगा। सरकार की यह नीति कि जिन क्षेत्रों में चावल की अत्यधिक खेती हो रही है, वहाँ की भूमि का उपयोग अब दलहन-तिलहन के लिए किया जाए, बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम है।

इस तकनीक से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सामाजिक स्वीकार्यता मिलने की संभावना अधिक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेकर लंबे समय से कई भ्रांतियां और आशंकाएं रही हैं, जैसे कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन जीनोम एडिटिंग में किसी बाहरी तत्व को शामिल नहीं किया जाता, जिससे यह नैतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक स्वीकार्य है। इससे किसानों को भी यह समझाना आसान होगा कि नई किस्में सुरक्षित हैं और उनकी उपज में लाभप्रद वृद्धि करेंगी।

भारत में कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में यह प्रयोग एक मील का पत्थर है। इससे पहले भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन तो बढ़ाया था, लेकिन उसमें रसायनों और जल का अत्यधिक उपयोग हुआ, जिससे भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब जबकि जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और जल संकट जैसे गंभीर मुद्दे सामने हैं, ऐसे में कम संसाधन खपत वाली उच्च उत्पादक किस्में ही टिकाऊ कृषि की कुंजी हो सकती हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जीनोम एडिटिंग की सहायता से विकसित की गई किस्में केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इन्हें व्यावसायिक रूप से किसानों तक पहुँचाने की योजना बनाई गई है। वैज्ञानिकों का यह प्रयास केवल अकादमिक उपलब्धि नहीं बल्कि व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को बीज वितरण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और बाजार संपर्क जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना होगा, ताकि किसान इसे सहजता से अपना सकें।

यह कहना बिलकुल उचित होगा कि जीनोम एडिटिंग जैसी उन्नत तकनीक के माध्यम से भारत न केवल अपनी कृषि प्रणाली को पुनः परिभाषित कर सकता है, बल्कि वैश्विक कृषि नवाचार के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, और पोषण की समस्याएँ वैश्विक स्तर पर चिंताजनक विषय बन गई हैं। ऐसे समय में यदि भारत जीनोम एडिटिंग के सफल प्रयोगों को बड़े पैमाने पर लागू करता है, तो यह न केवल भारत की कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि विश्व को भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह तकनीक पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में अधिक सटीक, तेज़ और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे फसलों की उपज बढ़ाने के साथ-साथ उनकी पौष्टिक गुणवत्ता में भी सुधार संभव हो पाता है।

विशेष रूप से चावल की दो नई किस्में, जिनका जीनोम एडिटिंग के माध्यम से विकास हुआ है, भारत के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि हैं। ये किस्में न केवल उच्च उपज वाली हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों जैसे सूखा, बाढ़ और तापमान में वृद्धि को सहन करने में भी सक्षम हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को हो रहे नुकसान को कम करने में ये फसलें सहायक सिद्ध होंगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, इन फसलों के पोषण स्तर में सुधार भी हुआ है, जो पोषण असंतुलन जैसी गंभीर समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। इससे बच्चों और वयस्कों दोनों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

भारत का कृषि निर्यात इस तकनीक से अत्यधिक लाभान्वित हो सकता है। विश्व बाजार में गुणवत्ता और टिकाऊ फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और जीनोम एडिटिंग से विकसित फसलों की वैश्विक स्वीकार्यता भारत के निर्यात को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही, यह तकनीक भारत को वैश्विक कृषि अनुसंधान और नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती है, जिससे नए अवसर पैदा होंगे और कृषि क्षेत्र में रोज़गार सृजन भी होगा।

हालांकि, इस तकनीक के समुचित और सुरक्षित उपयोग के लिए कुछ चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, जीनोम एडिटिंग की तकनीकी जटिलताओं को समझना और उन्हें सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करना अनिवार्य है ताकि वे इस नई तकनीक का सही फायदा उठा सकें। सरकार और संबंधित संस्थानों को एक व्यापक और ठोस नीति बनानी होगी, जो नैतिकता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मानकों को सुनिश्चित करे। साथ ही, इस तकनीक के उपयोग पर निगरानी व्यवस्था भी प्रभावी रूप से स्थापित करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग को रोका जा सके।

यह भी आवश्यक है कि जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों के आधार पर हो, न कि केवल आर्थिक लाभ के लिए। इसके लिए वैज्ञानिक समुदाय, नीति निर्माता, किसानों और आम जनता के बीच एक स्पष्ट संवाद और सहयोग स्थापित करना होगा। इस संवाद के माध्यम से ही तकनीक के प्रति भरोसा और स्वीकृति बढ़ेगी, जिससे इसका व्यापक और सफल उपयोग संभव होगा। भारत में जीनोम एडिटिंग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रारंभ हो चुका है। यदि इस क्रांति को मजबूत नीति समर्थन, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनसमर्थन प्राप्त होता है, तो यह बीज निश्चित रूप से एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भारत के निर्माण में फल-फूल कर बड़ा पेड़ बन जाएगा। यह तकनीक न केवल भारत के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाएगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व को एक स्थिर और सुरक्षित खाद्य भविष्य की ओर ले जाएगी। इससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक सुधार आएगा, बल्कि भारत की ग्रामीण संस्कृति और आत्मा में भी एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होगा। यह तकनीक, इस अर्थ में, केवल कृषि का नवाचार नहीं बल्कि देश के हर किसान के जीवन में सुधार और उज्जवल भविष्य की एक नई किरण है।

पर्यावरण

प्रो. अस्मिता सिंह

लेखक शोधार्थी हैं।

प्रकृति को रौंदकर न बनें विकास का रास्ता

अधिकार जिम्मेदारी के साथ ही मिलते हैं, भारत का संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, लेकिन साथ ही उन्हें सजग संरक्षक भी बनाता है। जहां अनुच्छेद 21 का विस्तार स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार देता है वहीं अनुच्छेद 48(क) और 51(क)(छ) पर्यावरण संरक्षण को राज्य और नागरिक दोनों का कर्तव्य घोषित करते हैं। यही कारण है कि जब लोग पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वह आंदोलन नहीं, बल्कि संविधान का जीता जागता रूप बन जाता है।

बीते माह हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। ठिठुरती जनवरी में जब तिरंगा आसमान में लहराता है, तब गणतंत्र दिवस सिर्फ़ एक औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर हमें सजग भी करता है कि हम केवल दर्शक नहीं, बल्कि संविधान से शक्ति पाए हुए नागरिक हैं। यह वह क्षण होता है जब जन-गण-मन की सामूहिक चेतना राष्ट्र के स्वर में बदलती है और वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, बल्कि धरती के प्रति कृतज्ञता का भाव बन जाता है। यह दिन वह स्मृति है जिसने सत्ता को जनता के हाथों में सौंपा और हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य भी दिए। इस कर्तव्य में देश की सीमाओं की रक्षा जितनी अहम है, उतनी ही ज़रूरी है उसकी नदियों, पहाड़ों, जंगलों और जीवन-प्रणालियों की हिफ़ाज़त करना।

अधिकार जिम्मेदारी के साथ ही मिलते हैं, भारत का संविधान नागरिकों को अधिकार देता है, लेकिन साथ ही उन्हें सजग संरक्षक भी बनाता है। जहां अनुच्छेद 21 का विस्तार स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार देता है वहीं अनुच्छेद 48(क) और 51(क)(छ) पर्यावरण संरक्षण को राज्य और नागरिक दोनों का कर्तव्य घोषित करते हैं। यही कारण है कि जब लोग पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वह आंदोलन नहीं, बल्कि संविधान का जीता जागता रूप बन जाता है।

पिछले वर्षों में देश ने ऐसे कई क्षण देखे हैं जहाँ जनता की सामूहिक चेतना ने प्रकृति को विनाश से बचाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हर्षिल और भैरव घाटी इसका ताज़ा उदाहरण है। दरअसल, चारधाम ऑल-वेदर रोड परियोजना के तहत यहाँ छह हज़ार से अधिक देवदार के पेड़ों को काटने का निर्णय लिया गया था। लेकिन स्थानीय निवासियों, पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेड़ों को भाई मानते हुए उन पर रक्षा-सूत्र बाँधे। यह दृश्य केवल विरोध नहीं था, यह हिमालय से किया गया संवाद था 'हिमालय है तो हम हैं।' दिलचस्प यह है कि इस शांत लेकिन दृढ़ प्रतिरोध के बाद सड़क चौड़ीकरण के मानक बदले गए और कटने वाले पेड़ों की संख्या प्रभावित हुई। हालांकि यह पूरी जीत नहीं थी, पर यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि जन-शक्ति नीति को भी मोड़ सकती है।

इसी तरह अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया हस्तक्षेप भी जनता की चेतना का परिणाम है। केन्द्रीय समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर अरावली की जिस नई परिभाषा को स्वीकार किया गया था, उस पर न्यायालय ने रोक लगाई। दरअसल, यह मामला केवल कानूनी व्याख्या का नहीं था, बल्कि उस पारिस्थितिकी की रक्षा का था जो दिल्ली-एनसीआर की साँसों से जुड़ी है। जनदबाव, विशेषज्ञों की आवाज़ और नागरिक चेतना ने अदालत को पुनर्विचार के लिए विवश किया। यह गणतंत्र की जीवित प्रक्रिया है।

दक्षिण भारत में हैदराबाद का गाछीबोवली क्षेत्र भी इसी क्रम की कड़ी है। शहरी विस्तार के नाम पर हरित क्षेत्रों को निगलने की कोशिशों के विरुद्ध जब नागरिक, छात्र और पर्यावरण समूह एकजुट हुए, तब विकास की परिभाषा पर प्रश्न खड़े हुए। दिलचस्प यह है कि यहाँ विरोध केवल विकास बनाम पर्यावरण का था ही नहीं, बल्कि यह माँग थी कि विकास का रास्ता प्रकृति को रौंदकर नहीं, उसके साथ चलकर तय करें।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् में जिस धरती की वंदना होती है, वही धरती इन संघर्षों का केंद्र है। महानगरों में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नागरिक याचिकाएँ, नदियों की स्वच्छता को लेकर सामाजिक आंदोलनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ये सभी गणतंत्र की जीवंत मिसाल हैं।

हाल में कई विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को लेकर जनता की आपत्तियों ने नीतियों को पुनः विचार के लिए बाध्य किया। ग्राम सभाओं की सहमति के बिना वन क्षेत्रों में परियोजनाओं का विरोध, तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों द्वारा जैव-विविधता की रक्षा, और शहरी नागरिकों द्वारा हरित क्षेत्रों को बचाने के लिए संगठित प्रयास दर्शाते है कि लोकतंत्र में जनता केवल दर्शक नहीं, निर्णायक शक्ति है।

पिछले वर्ष भी जल संकट, वन कटान और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर जन-भागीदारी ने शासन को अधिक उत्तरदायी बनाया। कई स्थानों पर स्थानीय समुदायों ने वर्षा जल संचयन, सामूहिक वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त अभियानों को जन-आंदोलन का रूप दिया।

भारत आज दुनिया में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि सरकारी नीतियों के साथ ही उन असंख्य नागरिकों की है जिन्होंने जंगल, नदी और वन्यजीव को अपनी सांस्कृतिक विरासत माना और उसे बचाया।

कटते जंगल, खनन, अंधाधुंध शहरीकरण और जलवायु संकट जैसी चुनौतियाँ अभी भी हमारे सामने हैं, लेकिन अब जनता की जागरूकता यह साबित करती है कि हमारा गणतंत्र केवल नाम का नहीं है। यह सक्रिय और सचेत है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल मतदान में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक सहभागिता में निहित है। जब जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, तब पर्यावरण संरक्षण नीति के साथ जन-आंदोलन बन जाता है। यही शक्ति आज भारत में पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षा-कवच बनकर उभर रही है।

आज जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं, तो संकल्प लें कि भारत माता की वंदना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। हम उसका प्राकृतिक वैभव बचाएंगे, उसकी नदियों, जंगलों और हवा की रक्षा करेंगे। क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो अपने नागरिकों के साथ उनके विकास और खुशहाली के पक्ष में खड़ी हो और यही है हमारे गणतंत्र की असली शान।

दृष्टिकोण

सत्यप्रकाश नायक

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

दिव्यांग महिलाओं की राह आसान बनाने की जवाबदेही

भारत में दिव्यांग महिलाओं की स्थिति को केवल स्वास्थ्य, सहायता या कल्याण की समस्या के रूप में देखना एक गंभीर भूल होगी। यह मूलतः सत्ता, संसाधनों, अवसरों और निर्णय-प्रक्रियाओं तक असमान पहुँच की समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 16 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन जी रही है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 2.7 करोड़ लोग दिव्यांग हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। इसके बावजूद नीति-निर्माण, योजनाओं और सामाजिक विमर्श में उनकी उपस्थिति अत्यंत सीमित बनी हुई है। वे सरकारी रिपोर्टों में दर्ज तो होती हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई देती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) और जनगणना के आँकड़े भी यह संकेत देते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में दिव्यांग महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है।

दिव्यांग महिला का जीवन तीन स्तरों पर नियंत्रित होता है: घर, समाज और व्यवस्था। घर के भीतर पिता, भाई और पति स्वयं को 'संरक्षक' मानते हुए उसकी हर पसंद पर अधिकार जताते हैं। निर्णय-प्रक्रियाओं पर पुरुषों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। समाज उसे 'कमज़ोर' और 'निर्भर' मानकर हाशिये पर रख देता है। और व्यवस्था उसे प्राथमिकता सूची के अंत में पहुँचा देती है। इन तीनों स्तरों पर पितृसत्तात्मक शक्ति-संबंध उसके जीवन की दिशा तय करते हैं।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, एनसीपीईडीपी, यूएन वीमेन इंडिया और सामाजिक शोधकर्ता अनीता घई के अध्ययन बताते हैं कि कई परिवारों में बेटियों को चाहे वे दिव्यांग हों या न होंआर्थिक निर्णयों और संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी भागीदारी नहीं मिलती। लेकिन जब बेटी दिव्यांग होती है, तो यह उपेक्षा और गहरी हो जाती है। उसे अक्सर 'दीर्घकालिक आश्रित' मान लिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि वह भविष्य में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। इसी सोच के कारण उसकी शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता पर पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता। धीरे-धीरे उसे आर्थिक रूप से निर्भर बना दिया जाता है। विवाह को ही उसका 'सुरक्षित भविष्य' मान लिया जाता है, और कई बार यह निर्णय उसकी इच्छा और सहमति के बिना होता है।

उसकी आवाजाही पर भी नियंत्रण रहता है कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, कब बाहर निकलेगीइन सब पर परिवार का अधिकार माना जाता है। 'इज़्ज़त', 'सुरक्षा' और 'देखभाल' के नाम पर यह नियंत्रण जीवनभर चलता रहता है। यह नियंत्रण उसके आत्मविश्वास और सामाजिक विकास को सीमित कर देता है। सवाल यह है कि हम सच में सुनते हैं कि वह क्या चाहती है?

यौनिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकार भी इसी नियंत्रण संरचना का हिस्सा बन जाते हैं। अनेक महिलाओं के लिए गर्भनिरोध, गर्भधारण या नसबंदी उनके स्वयं के निर्णय नहीं होते। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्टें बताती हैं कि कई मामलों में दिव्यांग महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में स्वतंत्र भूमिका नहीं मिलती। डॉक्टर भी अक्सर महिला से सीधे बात करने के बजाय परिवार से संवाद करना अधिक सुरक्षित समझते हैं। यह स्थिति महिला की इच्छा, सहमति और गरिमा को कमजोर करती है।

हम अक्सर 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे यह एक समान स्थिति हो, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बौद्धिक दिव्यांगता, मनोसामाजिक दिव्यांगता, ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी महिलाओं की ज़रूरतें, क्षमताएँ और चुनौतियाँ अलग-अलग होती हैं। फिर भी हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ इस विविधता को गंभीरता से नहीं समझतीं।

मनोसामाजिक और बौद्धिक दिव्यांगता से जुड़ी महिलाओं को अक्सर 'निर्णय लेने में अक्षम' मान लिया जाता है। उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी लड़कियों को कई विद्यालय 'मैनेज नहीं कर पाने' का बहाना बनाकर बाहर कर देते हैं। प्रारंभिक पहचान, थेरेपी और पुनर्वास सेवाओं की कमी उन्हें जीवनभर पीछे धकेल देती है। विशेष शिक्षकों, काउंसलरों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती है।

शिक्षा से बाहर होना आगे चलकर रोजगार के अवसरों को लगभग समाप्त कर देता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार दिव्यांग महिलाओं की श्रम भागीदारी सामान्य महिलाओं की तुलना में काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्हीलचेयर, स्क्रीन रीडर, श्रवण यंत्र, फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग जैसी सुविधाएँ आज भी सीमित हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने नए अवसर दिए हैं, लेकिन डिजिटल असमानता ने नए बहिष्करण भी पैदा किए हैं। बहुत-सी महिलाओं के पास न स्मार्टफोन है, न इंटरनेट, न प्रशिक्षण। वे बैंकिंग, पेंशन और सरकारी पोर्टलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, जिससे शोषण का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी यही असमानता दिखती है। डब्ल्यूएचओ, ह्यूमन राइट वॉच और एम्स-आधारित अध्ययनों में दर्ज है कि कई मामलों में दिव्यांग महिलाओं को स्वतंत्र निर्णयकर्ता नहीं माना जाता। इलाज की प्रक्रिया में उनकी आवाज़ कमजोर पड़ जाती है।

भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और संयुक्त राष्ट्र की दिव्यांग अधिकार संधि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भागीदारी का अधिकार देती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य भी समावेशन पर ज़ोर देते हैं। इनमें लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य 8 सम्मानजनक रोजगार और लक्ष्य 10 असमानता घटाने से जुड़े हैं। इन सभी का सीधा संबंध दिव्यांग महिलाओं के जीवन से है।

लेकिन कमजोर क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय की कमी और स्थानीय निगरानी के अभाव ने इन प्रावधानों को काग़ज़ों तक सीमित कर दिया है। आज सबसे बड़ी समस्या जवाबदेही की है। ज़िला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण दुर्लभ हैं। मोनिटरींग रिपोर्टें औपचारिक बनकर रह जाती हैं। लापरवाही पर शायद ही कभी ठोस कार्रवाई होती है। नतीजतन हमें यह स्पष्ट नहीं पता कि कितनी दिव्यांग लड़कियाँ पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है, और कितनी को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हुई हैं।

दिव्यांगता को समझने के लिए 'इम्पाइरमेंट', 'डियाबिलिटी' और 'हैन्डीकैप' के अंतर को समझना आवश्यक है। इम्पाइरमेंट शरीर या मस्तिष्क की जैविक स्थिति हैमानव विविधता का हिस्सा। डियाबिलिटी तब बनती है जब कुछ काम कठिन हो जाते हैं। सही सहयोग मिलने पर इन्हें कम किया जा सकता है। लेकिन जब स्कूलों में रैम्प नहीं होते, बसों में सुविधा नहीं होती, अस्पताल महिला से नहीं बल्कि परिवार से बात करता है, तब यह स्थिति हैन्डीकैप बन जाती है। तब समस्या शरीर में नहीं, हमारी व्यवस्था में बस जाती है।

एक गाँव में रहने वाली सीमा, जो ऑटिज़्म से जुड़ी चुनौतियों के साथ जीवन जी रही है, यह जानना चाहती है कि उसके आसपास सुरक्षित सार्वजनिक स्थान कहाँ है। दीपक यह जानना चाहता है कि उसके ब्लॉक में शुरुआती पहचान का केंद्र कहाँ है। कई बच्चे यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके शिक्षक उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। कहीं कोई युवती रोजगार खोज रही है। कहीं कोई माँ पुनर्वास सेवा ढूँढ रही है।

ये सभी सवाल किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं। ये उस पूरी व्यवस्था से जुड़े हैं, जो योजनाएँ तो बनाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाती। जब किसी महिला को अपने ही अधिकारों, सेवाओं और सहायता के लिए भटकना पड़े, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या उसकी क्षमता में नहीं, हमारी व्यवस्था में है।

दिव्यांग महिलाएँ किसी विशेष सहानुभूति की नहीं, बल्कि समान अधिकार और समान अवसर की पात्र हैं। उनके भीतर नेतृत्व, रचनात्मकता और समाज में योगदान देने की पूरी क्षमता है। लेकिन हमारी सामाजिक और प्रशासनिक संरचनाएँ अक्सर इन क्षमताओं को पहचानने और आगे बढ़ाने में असफल रहती हैं।

असल प्रश्न यह नहीं है कि दिव्यांग महिलाएँ क्या कर सकती हैं या क्या नहीं कर सकतीं। असल प्रश्न यह है कि क्या हमारी व्यवस्था उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर देती है, क्या हम उन्हें निर्णय-प्रक्रियाओं में वास्तविक भागीदारी देते हैं, और क्या हम उन्हें पूर्ण नागरिक के रूप में स्वीकार करते हैं।

जब तक हम अपने बनाए हुए इन सामाजिक और संरचनात्मक अवरोधों को पहचानकर दूर नहीं करेंगे, तब तक समावेशन केवल नीतिगत दस्तावेज़ों और भाषणों तक सीमित रहेगा। वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है, जब नीति, प्रशासन और समाज तीनों मिलकर जिम्मेदारी लें।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करें कि कोई भी महिला केवल इसलिए पीछे न रह जाए, क्योंकि हमने उसके लिए सुलभ रास्ते नहीं बनाए। यही समावेशन का सच्चा अर्थ है एक ऐसा समाज, जहाँ समान अवसर, समान सम्मान और समान भागीदारी केवल आदर्श न होकर वास्तविकता बनें।

पुण्यतिथि पर विशेष

प्रमोद दीक्षित मलय
लेखक शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।

वासुदेव बलवंत फड़के: सशस्त्र क्रांति के पितामह

पुणे में स्थित सैन्य लेखा विभाग के अधिकारी कक्ष में घुसते ही उस 25 वर्षीय युवक ने अधिकारी की मेज पर एक तार रख छुट्टी देने हेतु प्रार्थना की। युवक के चेहरे पर अधीरता, व्याकुलता एवं व्यग्रता के भाव पसरे हुए थे, सांसें गहरी और धीमी हो गई थीं। अधिकारी ने तार पढ़ना शुरू किया, 'प्रिय वासु, मां मृत्युशय्या पर है। अंतिम दर्शन करने हो तो तुरंत घर आ जाओ।' अधिकारी ने युवक के चेहरे पर नजर गड़ाते हुए कहा कि काम की अधिकता है। छुट्टी नहीं मिलेगी। वह युवक मुड़ा और सीधे अपने गांव की ओर चल पड़ा। दुर्भाग्य! उसके पहुंचने से पूर्व ही मां स्वर्ग सिधार गयी थी। युवक का चेहरा तमतमा गया और अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले सशस्त्र विद्रोह की तैयारी में जुट गया और अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। उसके नाम से ही अंग्रेज भयाक्रांत हो जाते थे। इतिहास में उसे भारतीय उग्र राष्ट्रवाद का पितामह कहा गया तो सशस्त्र संघर्ष छेड़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी भी। वह युवक है वासुदेव बलवंत फड़के, जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजी सत्ता ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था।

वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म बाम्बे प्रेसीडेंसी अंतर्गत थाणे के निकट शिरढोण गांव में चितपावन ब्राह्मण परिवार में पिता बलवंत फड़के एवं माता सरस्वती बाई के घर हुआ था, जो अब रायगढ़ जिला में आता है। परिवार में बालक को सभी प्यार से वासु कहते थे। वासुदेव की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। मराठी के साथ ही आपने रुचि पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया और महारत हासिल की। पढ़ाई के साथ ही वासुदेव नियमित रूप से अखाड़े जाकर कुश्ती, तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करते थे। वह जब हाईस्कूल कर रहे थे, तब पिता ने पढ़ाई छोड़कर 10 रुपए मासिक पर एक व्यापारी के यहां नौकरी करने हेतु कहा। किंतु वासुदेव आगे पढ़ना चाहते थे, इसीलिए घर से वह मुम्बई चले गये और जीआरपी में 20 रुपए मासिक वेतन पर सेवा करते हुए वर्ष 1862 में मुम्बई विद्यापीठ से स्नातक पूर्ण किया। उस समय स्नातक पूर्ण करने वाले वह कुछ गिने-चुने लोगों में से एक थे। मानव जीवन में शिक्षा के महत्व से वह सर्वथा परिचित थे। तभी तो 1860 में आपने दो-तीन साथियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र एजुकेशन सोसायटी का गठन किया और पुणे में एक शिक्षा संस्थान खोला। आज इस सोसायटी द्वारा पूरे महाराष्ट्र में 75 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं।

वासुदेव बलवंत फड़के दो-तीन संस्थाओं में कार्य करते हुए अंततः 1865 में सैन्य लेखा विभाग में नौकरी पाकर पुणे आ गये। वह पुणे में भी कुश्ती के अभ्यास हेतु प्रसिद्ध पहलवान लाहुजी राघोजी साल्वे के अखाड़े में जाने लगे थे। लाहुजी पहलवानी के साथ ही युवाओं में राष्ट्रीयता का भाव भी भरते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने का आह्वान करते थे। वासुदेव लाहुजी साल्वे को अभिभावक एवं मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे। इसी बीच महादेव गोविंद रानाडे का पुणे में भाषण हुआ, जिसमें रानाडे ने अंग्रेजों द्वारा भारत की आर्थिक लूट एवं किसानों के शोषण सम्बंधित महत्त्वपूर्ण विचार जनता के समझ रखते हुए जन जागरण की अपील किया। उनके भाषण से वासुदेव बहुत प्रभावित हुए और उनको एक दिशा मिली। अब वासुदेव कार्यालय

से बचे समय का सदुपयोग आसपास के गांवों में लोगों से बातचीत करते हुए लोक जागरण में करने लगे। गांव-गांव घूम-घूम कर किसानों, युवाओं, मजदूरों, विद्यार्थियों और महिलाओं से गम्भीरता पूर्वक संवाद करने और लोगों को जगाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। इसके पूर्व 1859 में उनका विवाह सईबाई से हो चुका था और संतान के रूप में एक पुत्री मथुताई प्राप्त हुई थी, किंतु किसी रोग से पत्नी की वर्ष 1872 में मृत्यु हो गई। वासुदेव का दूसरा विवाह गोपिका बाई से 1873 में सम्पन्न हुआ। तत्कालीन समाज की सोच के विरुद्ध आपने पत्नी को पढ़ना-लिखना के साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई। इसी बीच माता सरस्वती बाई का निधन हुआ, जिसका प्रसंग लेख के आरम्भ में दिया गया गया और वासुदेव नौकरी का त्याग कर अंग्रेजों के विरुद्ध समाज संगठन के काम में जुट गये। 1875-76 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा, चतुर्दिक त्राहि-त्राहि मच गई। जनता के लिए भोजन का प्रबंध करना मुश्किल हो गया, ऊपर से अंग्रेजों का जुल्म-अत्याचार चरम पर था। इससे क्षुब्ध वासुदेव ने भील, कोली और धांगर जाति समूहों के युवाओं का 'रामोशी' नामक संगठन बना अंग्रेजी कोष लूटने हेतु पुणे निवासी अंग्रेजों के विश्वासपात्र व्यापारी के यहां रखे गये लगान और आयकर का रुपया छापा मार कर लूट लिया तथा भूखी जनता के भोजन का प्रबंध किया। अंग्रेजों की बड़ी किरकिरी हुई। अब अंग्रेज अधिकारी और सिपाही वासुदेव के पीछे पड़ गये। अंग्रेजों का सामना करने के लिए फ़रवरी 1879 में वासुदेव ने 300 आदमियों की एक सशस्त्र फौज बनाई और 13 मई, 1879 की अर्धरात्रि को एक अंग्रेजों के प्रमुख भवन को आग लगा दी, जिसमें अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक कार्यवाही चल रही थी। कुपित अंग्रेज अधिकारी ने वासुदेव को पकड़ने हेतु 50 हजार का इनाम घोषित किया। अगले ही दिन वासुदेव फड़के ने पलटवार करते हुए अपने हस्ताक्षर से मुम्बई में इश्तहार लगवा दिये जिसमें गवर्नर रिचर्ड का सिर काटने वाले को 75 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इससे अंग्रेज बौखला गये। वासुदेव को पकड़ने हेतु पूरी ताकत झोंक दी और वासुदेव के बहुत साथियों को पकड़ लिया या मार दिया। अपनी ताकत कम देख संयम से काम लेते हुए वासुदेव हैदराबाद निकल गये किंतु अंग्रेजों और निजाम हैदराबाद की सेना संयुक्त रूप से वासुदेव को घेरने लगी। एक स्थानीय निवासी ने इनाम के प्रलोभन में एक मंदिर में शरण लिए वासुदेव बलवंत फड़के का पता अंग्रेजों को दे दिया। 20 जुलाई, 1879 को बीजापुर के देवर नवादगी ग्राम के मंदिर में सोते समय वासुदेव को गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। तत्पश्चात राजद्रोह का मुकदमा चला, आजन्म कारावास की सजा हुई और भारत की मुख्य भूमि से दूर मध्य-पूर्व देश यमन की अदन जेल में कैद कर अमानवीय यातनाएं दीं। उनको तपेदिक रोग हो गया और 17 फरवरी, 1883 को भारत माता के इस महान सपूत ने स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके बलिदान को नमन कर भारत सरकार ने वर्ष 1984 में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। मुम्बई के चौक का नामकरण उनके नाम पर हुआ और गिरफ्तारी स्थल को एक स्मारक के रूप में सुसज्जित किया ताकि आने वाली पीढ़ी भारत के उस महान क्रांतिकारी के योगदान से परिचित हो सके जिसके नामोल्लेख मात्र से आजादी के आंदोलन में युवाओं में त्याग एवं बलिदान की भावना बलवती होती रही। वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि पर देश श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है।

राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहा वसूली अभियान

एसडीएम के नेतृत्व में आज हुई ढाई लाख रुपए की रिकवरी

बैतूल। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देशन में एवं एसडीएम बैतूल डॉ अभिजीत सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगान वसूली अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। 60000 रुपए की राशि वसूली की गई। इसके अलावा अन्य बकायादारों से भी वसूली की गई, कुल वसूली 250000 रुपए की गई। बैतूल एसडीएम डॉ अभिजीत सिंह ने बकायादारों से आग्रह

इस अभियान के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक भीमराव पोर्टफोड़े ने बताया कि यह अभियान वित्तीय वर्ष 2025-26 की बकाया राशि की वसूली के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज संदेश तातेड कोठीबाजार बैतूल से किया है कि वे अपनी बकाया राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व जमा करा देवें और पेनाल्टी से बचें। राजस्व विभाग की टीम में राजस्व निरीक्षक भीमराव पोटफोडे, धनराज झललारे, गोपाल महसकी, धर्मेंद्र पवार, महेश उइके, जितेंद्र पवार आदि सम्मिलित हैं।

टॉयलेट क्लीनर का ढक्कन खुलते ही फैली जहरीली गैस

बैतूल। टॉयलेट क्लीनर की गैस की चपेट में आकर एक ही परिवार के तीन लोग बेहोश हो गए। बुजुर्ग पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जबकि मां और बेटे वार्ड में भर्ती हैं। मामला कोतवाली थाना इलाके के टेमनी गांव में सोमवार का है। स्थानीय निवासी चंदन सुबह अपने घर के टॉयलेट की सफाई कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने एसिड युक्त टॉयलेट क्लीनर की बोतल खोलनी चाही, वह तेज दबाव के साथ खुल गई। इससे एसिड बाहर छलक गया और बाथरूम में जहरीली गैस फैल गई। इसके संपर्क में आते ही चंदन को घबराहट और सांस लेने में तकलीफ होने लगी।

प्रेम प्रसंग में महाराष्ट्र के युवक की निर्मम हत्या, शव खेत में दफनाया

भैंसदेही पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया अंधेकत्ल का खुलासा, तीन आरोपी पुलिस गिरफ्त में

बैतूल। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की निर्मम हत्या कर परिजनों ने शव को खेत में दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। खासबात यह है कि जिले में विगत एक माह के भीतर अवैध संबंध/प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की यह चौथी गंभीर घटना है, जो सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों के क्षरण की चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। पुलिस जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को थाना भैंसदेही को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोडिया में एक मोटरसाइकिल बिना चालक के खड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मोटरसाइकिल एमपी 48, एम 7850 विसराम साल्वे के घर के सामने खड़ी मिली। विसराम साल्वे घर पर नहीं मिला। उसकी पत्नी सोनाय साल्वे से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसका पति बाहर गया है तथा पुत्री सुमित्रा सातनेर चली गई है। मोटरसाइकिल चालक के संबंध में वह स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी एवं बार-बार बयान बदलती रही, जिससे संदेह गहराया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सोनाय साल्वे ने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चालक शिवम धुर्वे (निवासी महाराष्ट्र) उसकी पुत्री सुमित्रा से मिलने आया था। जहां कहासुनी होन पर उसकी हत्या कर दी और शव खेत में दफना दिया।

खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया शव- ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस पुराने खेत की ओर पहुंची। हिकमत अमली से पूछताछ में सोनाय साल्वे ने स्वीकार किया कि मोटरसाइकिल चालक शिवम धुर्वे (निवासी महाराष्ट्र) उसकी पुत्री सुमित्रा से मिलने आया था। आपसी कहासुनी के बाद विसराम साल्वे, सोनाय साल्वे एवं

सुमित्रा ने मिलकर शिवम के साथ मारपीट की। आरोपियों ने मृतक को थप्पड़ एवं मुक्कों से पीटा, उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए तथा उसे जंगल स्थित खेत में ले गए। वहां सुमित्रा के पिता विसराम साल्वे ने पत्थर पटककर एवं डंडों से वार कर उसकी हत्या कर दी। 13 फरवरी की सुबह आरोपियों ने खेत/जंगल क्षेत्र में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया, ताकि अपराध छुपाया जा सके।

पुलिस ने युवक का शव किया बरामद - एसडीएम भैंसदेही को सूचना देकर वैधानिक प्रक्रिया के तहत तहसीलदार एवं नगर परिषद टीम की उपस्थिति में उत्खनन कराया गया। वीडियोग्राफी के साथ कार्यवाही करते हुए लगभग 25-30 वर्षीय पुरुष का शव बरामद किया गया। शव को पीएम के लिए सीएचसी भैंसदेही की मर्चुरी में सुरक्षित रखा गया। 15 फरवरी को शासन तर्फे उपनिरीक्षक रामप्रकाश कीर की रिपोर्ट पर थाना भैंसदेही में धारा 103(2), 326(बी), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने सुमित्रा मौसिक, विसराम साल्वे (पिता) और सोनाय साल्वे (माता) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

युवक को फोन कर मायके बुलाया और कर दी हत्या- मृतक शिवम धुर्वे आरोपिया सुमित्रा मौसिक का परिचित था, तथा उसके पीछे पड़ा हुआ था एवं उस पर बुरी नियत रखता था। सुमित्रा विवाहित थी एवं उसके दो बच्चों के साथ ग्राम सातनेर में रहती थी, उसका पति महाराष्ट्र में मजदूरी करता था, जो जनवरी माह में घर लौट आया था। मृतक द्वारा आरोपिया को लगातार परेशान किया जा रहा था एवं धमकाया जा रहा है। इससे परेशान होकर सुमित्रा ने मृतक को 13 फरवरी को अपने मायके ग्राम कौडि?ा बुलाया। माता-पिता के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे जंगल में स्थित खेत में ले गए, जहां सुमित्रा मौसिक के पिता विसराम साल्वे द्वारा मृतक के सिर पर पत्थर पटककर एवं डंडों से मारकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से आरोपी विसराम साल्वे के खेत/जंगल क्षेत्र में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया गया।आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

स्थानीय निकाय की वार्षिक मतदाता पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बैतूल कलेक्टर सम्मानित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल एवं एसडीएम भैंसदेही को भी मिला सम्मान

बैतूल। स्थानीय निकाय की वार्षिक मतदाता पुनरीक्षण कार्य तथा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 (उत्तरार्द्ध) को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकाय नगर पालिका, नगर परिषद् और पंचायत की मतदाता सूचियों के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्य माह अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर नवंबर 2025 की अवधि में किया गया था। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के मार्गदर्शन एवं माइक्रो मॉनिटरिंग में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को भोपाल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ. पी. रावत, पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम और आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश मनोज श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर श्री सूर्यवंशी को सम्मान प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में जिले से उत्कृष्ट कार्य के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल मकसूद अहमद तथा एसडीएम भैंसदेही अजीत मरावी को भी सम्मानित किया गया। अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आयोग की समय सीमा में प्राप्त दावे आपत्तियों की जांच एवं निराकरण कर मतदाता सूची को अद्यतन बनाने में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के सागर एवं दमोह जिलों को भी सम्मानित किया गया। बैतूल जिले की इस उपलब्धि से प्रशासनिक कार्यकुशलता , टीम वर्क एवं निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती है।

नर्मदापुरम जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

महाशिवरात्रि पर्व पर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने पचमढ़ी ,अपर कलेक्टर राजीव रंजन ने सोहागपुर में किया निरीक्षण

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। मध्यप्रदेश का नर्मदापुरम धार्मिक एवं पुरातत्व का स्थल है। जिसमें पचमढ़ी महादेव, चौरागढ़ मंदिर , सोहागपुर में 16 वीं सदी की शिव पार्वती की आलिंगनबद्ध पाषाण प्रतिमा, इटारसी में तिलक सिन्दूर एवं शरद देव मंदिर , नर्मदापुरम में काले महादेव, सिवनी मालवा में गणेश,शिव मंदिर एवं आंवली घाट पर स्थापित में शिव प्रतिमा स्थापित हैं। विश्व विख्यात पचमढ़ी में चौरागढ़ 4हजार फुट से अधिक ऊंचाई पर मंदिर प्रदेश के ही नहीं महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। महाराष्ट्र एवं आस-पास के श्रद्धालु मिन्नतें पूर्ण होने पर अपने कंधों पर भारी भरकम त्रिशूल लेकर श्रद्धा के मंदिर परिसर में अर्पित करते हैं। उल्लेखनीय है कि चौरागढ दुर्गम मार्ग होने के बाबजूद पूरी श्रद्धा के भक्त जा रहे हैं। शिवरात्रि पर्व पर करीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ज्ञातव्य है कि पचमढी को भगवान शिव की तपस्या स्थली माना जाता है। किंवदंतियां हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागरिक भगवान

शिव को अपना बहनोई तथा देवी पार्वती को अपनी बहन मानते है। इस प्राचीन आस्था के केंद्र पर भगवान चौड़ेश्व ंमंदिर में भगवान भोलेनाथ की प्राचीन शिवलिंग सहित मनमोहक प्रतिमा और चौरा बाबा की प्रतिमा भी स्थापित है। एक अन्य किवदंती के अनुसार चौरा महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर वर प्रदान किया था कि, यहां दर्शन करने से सभी को मनोकना पूर्ण होगी। भक्तों की मन्नत पूर्ण होने पर यहां त्रिशूल चढ़ाने की परम्परा है। मंदिर परिसर में अर्पित त्रिशूलों का अंबार लगा हुआ है ।जो अपने आराध्य भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था एवं भक्ति को परिलक्षित करता है। पचमढ़ी जटाशंकर महादेव एवं गुप्त महादेव को भी अपने पौराणिक महत्व को समेटे हुए हैं।

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने देर रात पचमढ़ी में महादेव मेले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उपस्थिति को लेकर वहां चल रही समस्त गतिविधियों का जायजा लेकर सभी संबंधित अधिकारियों से ससत मानिटिरिग करने के निर्देश दिए। आपके साथ एसपी सांई कृष्ण एस थोटा, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, पिपरिया एसडीएम सहित अन्य अधिकारी साथ थे। इधर सोहागपुर में राज्य मार्ग 22 नर्मदापुरम पिपरिया पर स्थित शिव पार्वती की आलिंगनबद्ध पाषाण प्रतिमा के शिव मंदिर में क्षेत्र के नागरिकों का आस्था, पौराणिक महत्व , शिल्प कला का संगम समाया हुआ है । क्षेत्र के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों, महिलाओं एवं युवक, युवतियों को निरंतर में दर्शनार्थ आना जाना आज ही जारी रहा। इसी व्यवस्था संबंध में अपर कलेक्टर राजीव रंजन पांडे महाशिवरात्रि मेले का निरीक्षण किया गया ।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी, तहसीलदार, आर एस झरबड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।महाशिवरात्रि पर नर्मदापुरम जिला श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है।

शंभू दरबार में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारूद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न

सोहागपुर। पलाश कालोनी शंभू दरबार में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।इस अवसर पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं महारुद्राभिषेक कार्यक्रम गृहस्थ संत पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल के सानिध्य में संम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अन्य नगरों के भक्त जन की उपस्थिति रही। भक्तों ने भगवान शिव पार्वती का अभिषेक पूजन करके पुन्य अर्जित किया ।मुख्य यजमान बंशीलाल सांखला ने बताया कि पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन पं.मनमोहन मुद्गल की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से हमारी सनातन संस्कृति की जागरूकता के लिए इसी तरह के धार्मिक आयोजन लगातार किए जाते रहे हैं हम सभी शिष्य परिवार आगे भी करते रहेंगे। चारों प्रहर की पूजन रुद्राभिषेक नमक चमक से आचार्य गौरीशंकर राजोरिया एवं पं.स्वदेश दुबे बरेली के द्वारा गृहस्थ साधक पं.प्रकाश मनमोहन जी मुद्गल के सानिध्य में संपन्न किया गया। पूजन में मिश्रीलाल साहू, महेश सोनी, शंकर सिंह चौहान,कैलाश सोनी, सौरभ अग्रवाल,कपिल पटवा, महेश,साहू,रामचरण पटेल,संजय दुबे,सालू भदौरिया, संजय किरार,राजेश पटेल, प्रीतम सिंह चौहान, अभिलाष दीक्षित, सौरभ रैकवार,सत्यम यादव,गौरशं मेहरा,हीरा विश्वकर्मा, गब्बर कहार, शम्भू ठाकुर, बंटी ठाकुर सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

जिले में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर दी गई स्वास्थ्य सेवाएं

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (एच.पी.एन.डी.) के अवसर पर समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार देहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के तहत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हितग्राहियों को आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श एवं सेवाओं का लाभ भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 0 से 1 वर्ष आयु वर्ग के 565 बच्चों का टीकाकरण किया गया, जबकि 1 वर्ष से अधिक आयु के 200 बच्चों को भी वैक्सीनेशन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 112 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित यह अभियान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नगद इनाम की घोषणा

विदिशा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के द्वारा थाना कोतवाली विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 036/2025 की विभिन्न धाराओ के फरार आरोपी कमलेश पुत्र सुंदर सिंह बिजौरिया निवासी ग्राम ढेकपुर थाना बैरसिया जिला भोपाल (म0प्र0) की सूचना देने वालो को तीन हजार रूपए की नगद राशि देने की उद्घोषणा की है। सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

विवाह समाराहों में हर्ष फायर प्रतिबंधित

हरदा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने जिले में विवाह समारोहों के दौरान बंदूक से हर्ष फायर करने पर रोक लगाई है। उन्होने कहा कि यदि कोई शस्त्र लायसेंसधारी ऐसा करता पाया जाता है तो उसके शस्त्र का लायसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

आयुष विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वृद्धजनों हेतु लगाए जा रहे विशेष शिविर

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले के वृद्ध एवं वरिष्ठजनों के स्वास्थ परीक्षण, योग अभ्यास एवं शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ पर ख्याल आदि कार्यक्रम के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को वृद्ध आश्रम में स्वास्थ्य के साथ योग शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धजनों को उनकी उम्र एवं स्थिति के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीनाक्षी चौरसिया की सलाह पर योग प्रशिक्षकों द्वारा योग अभ्यास कराया गया। साथ ही स्वस्थ रहने संबंधित सलाह दी गई। उन्होने जिले के सभी सामान्य वृद्धजन एवं आम नागरिकों से आग्रह किया है कि सभी शिविरों में उपस्थित होकर स्वास्थ सेवाओं का लाभ लें। वृद्धजनों, वरिष्ठों एवं आमजनों के लिए स्थानीय वृद्ध आश्रम में आगामी 19, 20 एवं 26, 27 फरवरी को सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित किए जाएंगे।

संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में किए जा रहे हैं शिविर

रायसेन (निप्र)। जिले में चलाए जा रहे संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के साथ ही शासन की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इन शिविरों के प्रभावी और सफल आयोजन हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिला अधिकारियों की शिविरों में ड्यूटी लगाई गई है। जिला अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों का निरीक्षण करने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्राम पंचायत टिमरावन में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्राप्त अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही कर निराकरण किया जा रहा है। शिविर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन के महाप्रबंधक श्री अजय सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खारी एवं बिलकिसगंज में ईको-फ्रेंडली ईंटों से निर्मित होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के होम-स्टे

ग्रामीणों को पर्यटन से जोड़कर आय संवर्धन का अभिनव प्रयास

सीहोर (निप्र)। जिले के ग्रामीण अंचलों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना अब केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित न रहकर ग्रामीणों की आय वृद्धि का सशक्त माध्यम भी बनेगी। जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए जनपद पंचायत सीहोर अंतर्गत ग्राम खारी एवं बिलकिसगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले आवासों को होम-स्टे मॉडल पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस पहल के अंतर्गत निर्मित आवासों के निर्माण में पारंपरिक ईंटों के स्थान पर पूर्णतः इको-फ्रेंडली ईंटों का उपयोग किया जाएगा। राख एवं कृषि अवशेषों से निर्मित ये ईंटें थर्मल इंसुलेशन युक्त होने से ग्रीष्म ऋतु में घर को ठंडा तथा शीत ऋतु में गर्म बनाए रखने में सहायक होंगी। साथ ही इनसे निर्माण लागत में कमी आने के साथ बाह्य प्लास्टर की आवश्यकता भी न्यूनतम रहेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जिला पंचायत, ग्रामीण आवास योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को होम-स्टे संचालन हेतु प्रेरित एवं मार्गदर्शित किया जाएगा, ताकि वे अपने आवास को आय सृजन के साधन के रूप में विकसित कर सकें।

ग्राम बिलकिसगंज एवं खारी प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण परिवेश एवं शांत वातावरण के लिए विख्यात हैं। भोपाल के समीप स्थित होने के कारण यहां वीकेंड पर्यटन की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं।

वर्तमान में क्षेत्र में संचालित होम-स्टे पर्यटकों द्वारा निरंतर बुक रहते हैं। प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन से पर्यटकों को ग्रामीण जीवन शैली, पारंपरिक भोजन, खेत-खलिहानों की सैर तथा स्थानीय लोक संस्कृति का अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

होम-स्टे की संख्या में वृद्धि से ग्राम स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। महिला स्वसहायता समूहों एवं ग्रामीणों द्वारा हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पाद, देसी घी, अनाज एवं स्थानीय उत्पादों का विक्रय किया जा सकेगा। साथ ही लोकनृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को भी आय अर्जन का अवसर प्राप्त होगा।

सीहोर जनपद सीईओ श्रीमती नमिता बघेल ने बताया कि खारी एवं बिलकिसगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासों को होम-स्टे मॉडल पर विकसित करने हेतु हितग्राहियों को प्रेरित किया जाएगा। इको-फ्रेंडली ईंटों के उपयोग से निर्मित ये आवास टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल होंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाते हुए स्वरोजगार से जोड़ना तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। पर्यटकों की आवक बढ़ने से विलेज टूरिज्म को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

माखननगर में लापता 4 वर्षीय बालक एक घंटे में मिला

टीआई ने सोशल मीडिया के परिजनों को खोजा, नहलाकर कपड़े-चप्पल भी पहनाए

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के माखननगर टीआई अनूप उईके की तत्परता से लापता 4 साल का एक बालक अपने परिजन से मिल पाया। पुलिस निरीक्षक उइके ने सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे के परिजनों को एक घंटे में खोज निकाला। इतना ही नहीं टीआई ने बच्चे को नहलाया और फिर नए कपड़े चप्पल पहनाई। उसे नाश्ता भी खिलाया।

फिर बच्चे को परिजनों को सौंपा। टीआई के इस कार्य की परिजनों और ग्रामीण सराहना कर रहे है। मामला माखननगर का है। जहां शनिवार को आदिवासी समाज का एक 4 साल का बालक गुज्जरवाड़ा गांव पहुंच गया था। जिसे ग्रामीणों ने अकेला घूमते देखा। ग्रामीणों ने डॉयल 112 को कॉल कर बुलाया। पुलिस स्टॉफ बालक को थाने ले आया। थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके ने बच्चे को फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर परिजनों को खोजने का प्रयास किया। कुछ ही देर में उसके परिजनों थाने पहुंचे। थाना प्रभारी उइके ने बालक को नहलाकर उसके लिए नए कपड़े और चप्पल बुलाकर पहनाई। थाना प्रभारी उइके ने बताया बालक आदिवासी समाज से है। भटककर माखननगर से चार किमी दूर गुज्जरवाड़ा चला गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों को खोजा गया।

घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए निरंतर की जा रही है छापामार कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों, होटलों एवं प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसाय के लिए उपयोग करने वाली दुकानों एवं संस्थानों की जांच कर उपयोग किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं एवं कार्रवाई की जा रही है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश चंदेल ने बताया कि जांच के दौरान कुबेरेश्वर धाम स्थित 13 दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करते हुए 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकाश चंदेल एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा की गई।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तृतीय चरण

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक कर बाल विवाह रोकथाम की दी जानकारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसवा के मार्गदर्शन में सिरोंज परियोजना में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तृतीय चरण में बाल विवाह रोकथाम के संबंध में सेवाप्रताओं और आगनबाडी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

महिला बाल विकास विभाग विदिशा से बाल विवाह रोकथाम प्रभारी श्री मुकेश ताम्रकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तृतीय चरण में की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी गई। बाल विवाह रोकथाम में सेवाप्रताओं की अहम भूमिका के बारे में बताया गया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई।

बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 10 9 8 एवं पुलिस हेल्पलाइन 112 पर तत्काल देकर बाल विवाह को होने से पूर्व रोका जा सकता है। सेवाप्रताओं से अपील की गई कि वह किसी भी नाबालिग बच्चें के विवाह में शामिल न हो ,किसी भी प्रकार की सेवाएं न दें, बालक ध्बालिका की आयु संबंधी जानकारी परिजनों से एवं आसपास के लोगों से मालूम कर लें। सेवाप्रताओं और आगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई। बाल विवाह दंडनीय अपराध है । बाल विवाह न रचें , अपराध से बचें का नारा दिया गया। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक इमाबेला किस्पोट्टा, निर्मला इक्का, नसरीन खान, भावना बावलिया बद्री प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्रवाई

मिट्टी का अवैध परिवहन करते पकड़ाएं दो डंपर, ओवरलोड वाहन भी जब्त

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खनिज, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने बिना रॉयल्टी मिट्टी और रेत का परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की। कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देश पर टीम ने मोहासा क्षेत्र से मिट्टी से भरे दो डंपर पकड़े। इन डंपरों के ड्राइवर के पास रॉयल्टी रसीद नहीं थी। जब्त डंपरों के नंबर एमपी 16 एच 1782 और एमपी 37 जीए 2555 हैं। इन्हें आरटीओ कार्यालय परिसर में खड़ा कराया गया है।

ओवरलोड रेत के वाहन भी जब्त

जासलपुर से एक ट्रक (एमपी09जीजी2643) को ओवरलोड रेत ले जाते पकड़ा गया। वहीं इटारसी तहसील में रेत के सात ओवरलोड डंपर जब्त किए गए। इन वाहनों को कृषि उपज मंडी इटारसी और थाना रामपुर गुर्रा परिसर में सुरक्षित रखा गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम जय सोलंकी, जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पहले भी सामने आ चुके हैं मामले

9 फरवरी को मोहासा फेस-2 में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया था। एक मामला एडीएम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पहले 1800 घन मीटर मिट्टी के अवैध उत्खनन की बात भी सामने आई थी। लगातार कार्रवाई के बावजूद अवैध परिवहन के मामले सामने आना यह दिखाता है कि मिट्टी माफिया पर अभी पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं विद्यार्थी कल्याण एनटीएफ के अंतर्गत तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन

बैतूल (निप्र)। वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सरदार विष्णु सिंह उईके शासकीय महाविद्यालय सारनी बगडोना में राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनएफटी मानसिक स्वास्थ्य एवं विद्यार्थी कल्याण के अन्तर्गत तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य श्री प्रदीप पंद्राम एवं एनटीएफ नोडल अधिकारी डॉ. दीपक कुमार मानकर के संरक्षण में किया गया। इस कार्यशाला में श्री प्रदीप पंद्राम ने कहा कि प्रायः सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ तनाव होता है। सम्मान की चाह सभी में होती है। किसी का ज्यादा, तो किसी का कम सम्मान होना भी तनाव कारण है।

तनाव व्यक्ति के भीतर नही, बल्कि बाहरी परिस्थितियों के टकराव से उत्पन्न होता है। मनुष्य के भीतर तनाव बाहरी आवरण से आता है। इसे कम करने के लिए हमें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर अधिक से अधिक मोड़ने की कोशिश कर तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही आपने समस्त विद्यार्थियों एवं समस्त स्टाफ को यह तनाव प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से तनाव से बचने के लिए प्रेरित किया। इसके अन्तर्गत 'मैं अकेला नहीं हूँ' विषय पर विद्यार्थियों द्वारा समूह चर्चा भी की गई। छात्र भूपेन्द्र यादव ने कहा कि तनाव का कारण व्यक्ति खुद स्वयं है। व्यक्ति दूसरे के योग्यता को देखकर स्वयं की योग्यता का कम आकलन करता है, जो आगे चलकर तनाव का कारण बनता है। डॉ. गोलमन आहके ने कार्यक्रम का संचालन कर आभार व्यक्त किया तथा कहा कि विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद करियर प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ हरीश लोखंडे एवं डॉ राजेश कुमार हनोते, श्री मनोज नागले, श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, डॉ दशरु यदुवंशी, श्री उत्तम साहू, श्री दिनकर लिखितकर, श्रीमती अर्चना महाले, श्रीमती कविता धोटे, श्रीमती निकिता सोनी, श्रीमती दीपिका सोनी, श्रीमती अनीता नागले, श्रीमती गंगा चौरे, श्रीमती लक्ष्मी नागले श्रीमती श्री अनुज हलदार श्रीमती रीना उईके, सुश्री प्रियंका दवंडे एवं विद्यार्थी प्रज्ञा चतुर्वेदी, प्रगतिसिंह, अमन कश्यप, दुर्गेश वरकड़े, श्रेया परमार, पियूष पवार आदि उपस्थित रहे।

पचमढ़ी के चौरागढ़ मेले में 2 श्रद्धालुओं की मौत

नंदीगढ़ में 50 फीट गहरी खाई में गिरा नागपुर का युवक; बुजुर्ग की हार्ट अटैक से जान गई

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में चौरागढ़ बाबा के मेले में दर्शन करने आए दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक महिला लापता है। नंदीगढ़ पहाड़ी पर एक श्रद्धालु की 50 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई, जबकि दूसरे श्रद्धालु की दर्शन कर लौटते समय हार्ट अटैक से जान चली गई। शुक्रवार को घटना की सूचना के बाद एसडीईआरएफ और पुलिस की टीम ने खाई से शव निकाला।

पचमढ़ी पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर लिया है और शनिवार को लापता हुई महिला की संयुक्त रूप से सर्चिंग की जा रही है। खाई में गिरने वाले मृतक की पहचान 45 वर्षीय गणेश मानवतकर के रूप में हुई है। वे नागपुर के जयंतनगर (कलमना थाना क्षेत्र) के रहने वाले थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट से मृतक की पहचान हो पाई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि गणेश मानवतकर हर साल चौरागढ़ महादेव के दर्शन के लिए आते थे। वे 9 फरवरी को नागपुर से निकले थे और नांदिया की तरफ से उन्होंने पैदल चढ़ाई शुरू की थी। इसी दौरान नंदीगढ़ की पहाड़ी (ट्रैक) से वे 50 फीट गहरी खाई में गिर गए।

एसडीईआरएफ और सिविल डिफेंस ने निकाला शव: शुक्रवार को लोगों की सूचना पर 50 फीट गहरी खाई में शव गिरा देखा गया। इसके बाद एसडीईआरएफ एवं सिविल डिफेंस की संयुक्त टीम 50 फीट गहरी खाई में उतरी। टीम ने शव को उठाकर पुलिस के सुपुर्द किया। सूचना मिलने के बाद शनिवार को मृतक की पत्नी और बेटा नांदिया पहुंच गए हैं।

दर्शन कर लौट रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक: दूसरी घटना ग्राम नांदिया के पास पहाड़ उतरते समय हुई। यहां नसरुल्लागंज निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग मनोहर कास्दे की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। उनके साथियों ने बताया कि वे सभी चौरागढ़ महादेव के दर्शन करके पहाड़ी से नीचे उतरकर आ रहे थे। नांदिया से पहले बुजुर्ग को सीने में दर्द हुआ। उन्हें तत्काल अस्थाई मेडिकल कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

एक महिला के गिरने की भी सूचना, सर्चिंग जारी : शनिवार को श्रद्धालुओं ने पुलिस को एक और महिला के पहाड़ी से खाई में गिरने की सूचना दी। इस सूचना के आधार पर एसडीईआरएफ और पुलिस की टीम खोजबीन कर रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पचमढ़ी थाना प्रभारी पदम सिंह मौर्य ने बताया, 'दो लोगों की मौत हुई है। एक की खाई में गिरने से आई चोटों से हुई। दूसरी मौत श्रद्धालु की हुई।

औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

बैतूल (निप्र)। औद्योगिक क्षेत्र कोसमी स्थित एमपी विनीइयर्स प्राइवेट लिमिटेड में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। स्वास्थ्य टीम द्वारा श्रमिकों का वजन, ब्लड प्रेशर एवं रक्त जांच सहित सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच के दौरान जिन श्रमिकों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गईं, उन्हें आवश्यक औषधि प्रदान की गई तथा आगे के उपचार के संबंध में परामर्श दिया गया।

इस्तीफे की मांग पर भी विपक्ष में रार

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया और कांग्रेस ने भी राज्यपाल की अभिभाषण के दौरान मंत्रियों के इस्तीफा मांग कर हंगामादार शुरुआत की। उम्मीद थी कि इस मद्दे पर विपक्ष, सरकार को तगड़ा घेरेगा, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ने 'सेल्फ-गोल' की नई पटकथा लिख डाली। मंत्रियों के इस्तीफे की चिट्ठी क्या लिखी गई, कांग्रेस के भीतर ही एक नया 'महाभारत' शुरू हो गया। सूत्र कहते हैं कि पिछले

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

दिनों प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी ने विपक्ष के एक दायित्व वाले नेता जी का पारा सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है। नेता जी का तर्क है- 'मैदान मेरा, दायित्व मेरा, तो फिर ये अध्यक्ष जी सीधे बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं?' बिना विश्वास में लिए लिखे गए इस पत्र को नेताजी अपनी मर्यादा का अपमान मान रहे हैं। अब आलम यह है कि कांग्रेस ने सदन में भले ही सरकार से मंत्रियों का इस्तीफा मांगा, लेकिन इसमें कांग्रेस का दमखम नहीं दिखा। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने एक-दूसरे के इस्तीफे की दुआएं मांगना शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो चंबल संभाग से आते हैं ने तो यहां तक कह दिया कि चिट्ठी लिखना दायित्व संभालने वाले नेता जी को इग्नोर करने जैसा है। इसे कहते हैं- 'दुश्मन मिले न मिले, दोस्त ही काफी है!'

'तारीफ' की ऐसी मार... सीधे विभाग से बाहर!

प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक 'अपर मुख्य सचिव' साहब की किस्मत के चर्चे बड़े आम हैं। बेचारों को क्या पता था कि माननीय की 'नेकी' उनके कॅरियर के लिए आफत बन जाएगी। हुआ यूँ कि पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में माननीय ने एसीएस साहब की मेहनत और विभाग के प्रति उनकी रुचि के कसीदे पढ़ डाले। साहब भी तारीफ सुनकर 'हृदय में हरियाली' लिए गदगद घूम रहे थे। लेकिन, जैसे ही आईएएस अफसरों की नई तबादला सूची आई, साहब का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। न केवल तबादला हुआ, बल्कि उन्हें उनके पसंदीदा विभाग से भी बेदखल कर दिया गया। अब जानकर चुटकी ले रहे हैं कि सरकार में 'ज्यादा तारीफ, विदाई का संकेत होती है।' अगली बार से साहब शायद माननीय को देखकर रास्ता बदल लें, ताकि कोई और तारीफ न हो जाए!

'रेरा' : तालाबंदी या नई ताजपोशी?

रियल स्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) मप्र के गलियारों में इन दिनों सन्नाटा भी है और सुगबुगाहट भी। चर्चा है कि क्या सरकार इस संस्थान पर ताला जड़ने की तैयारी में है या फिर किसी चहेते की ताजपोशी होगी? सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने पहले ही आग लगा रखी है, ऊपर से 7 मार्च को वर्तमान अध्यक्ष एपी श्रीवास्तव साहब की 'रिटायरमेंट' की घंटी बजने वाली है। पद खाली हैं, काम अटके हैं और सरकार की खामोशी डरा रही है। बिल्डरों और खरीदारों के बीच के इस 'अंपायर' की स्थिति फिलहाल उस लावारिस मकान जैसी हो गई है, जिसका न कोई खरीदार है और न ही रखवाला। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार यहाँ कोई नया 'खेला' करती है या रेरा को इतिहास के पन्नों में समेट देती है।

वाह क्या बात है, साहब की 'हैट्रिक'

एक आईएएस साहब ने निजी जीवन में 'हैट्रिक' लगाकर सबको हैरान कर दिया है। साहब ने पिछले डेढ़ दशक में तीन शादियों का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो किसी भी नेशनल पार्क के 'सफारी' से ज्यादा रोमांचक है। हाल ही में एक मशहूर नेशनल पार्क में साहब ने अपना तीसरा ब्याह रचाया। किस्सा और भी दिलचस्प है। साहब की तीनों पत्नियां भी आईएएस ही हैं। पहली से तलाक, दूसरी से बिछोह और अब तीसरी के साथ नई पारी! मजेदार बात यह है कि एक पूर्व पत्नी वर्तमान में एक जिले की कलेक्टर हैं, तो दूसरी मंत्रालय की फाइलें निपटा रही हैं। साहब का राजनीतिक रसूख भी ऐसा है कि तबादलों के दौर में उनका 'कलेक्शन' कभी खराब नहीं होता। प्रशासन के गलियारों में चर्चा है कि साहब को गवर्नेंस से ज्यादा 'गठबंधन' की अच्छी समझ है!

मुस्लिम चचेरी बहनों ने हिंदू चचेरे भाइयों से शादी की

वीडियो में कहा- छतरपुर एसपी साब, हमारे परिवार जान से मारने की धमकी दे रहे, सुरक्षा दें

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर में 9 फरवरी से लापता दो मुस्लिम चचेरी बहनों ने दो हिंदू चचेरे भाइयों से शादी कर ली। दोनों ने अपने पतियों के साथ वीडियो बनाकर रविवार को जारी किया। इसमें एसपी से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि हमारे ससुराल पक्ष को परेशान न किया जाए। वीडियो में युवतियों ने कहा- अगर उनके परिवार के लोगों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी मायके पक्ष की होगी।

मामला जिले के नौगांव का है। दोनों युवतियां एटीएम से रुपए निकालने के नाम पर घर से निकली थीं, लेकिन घर नहीं लौटीं। परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत में लड़कियों को नाबालिग बताया था। उनका आरोप था कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही। समाज के महिला-पुरुष थाने पहुंचे और प्रदर्शन भी किया था।

प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने अपने बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना था कि शिकायत के बावजूद पुलिस दूसरे पक्ष के आने का इंतजार कर रही थी, जिससे महिलाओं में आक्रोश फैल गया और हंगामा हुआ।

वीडियो जारी कर कहा- हम सुरक्षित हैं, किसी दबाव में नहीं- वीडियो में युवतियां कर हिंदू युवकों से शादी करने और अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कह रही हैं। दोनों युवतियां खुद को बालिग बताते हुए कह रही हैं

कि उन्होंने अपनी मर्जी से नगर के ही दो चचेरे भाइयों से शादी की है। उन्होंने कहा वे सुरक्षित हैं और किसी दबाव में नहीं हैं।

पुलिस बोली- परिजन अपहरण की आशंका जता रहे थे- टीआई बाल्मिक चौबे ने बताया कि दोनों युवतियों की गुमशुदगी दर्ज थी। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे थे। दोनों युवतियां बालिग हैं और चचेरी बहनें हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उनकी बरामदगी में लगी है। लड़कियों के बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग केस- पीड़िता की तबीयत बिगड़ी

चार दिन अस्पताल में भर्ती रही, एफआईआर दर्ज कराने के बाद से बीमार है

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार, छात्रा मानसिक रूप से परेशान है और डॉक्टरों की सलाह पर उसे चार दिन तक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रविवार को उसकी हालत में सुधार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) कर रही है। एसआईटी प्रमुख अंकिता खातरकर ने बताया कि एक आरोपी को न्यायालय से रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी मोबाइल फोन के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मोबाइल को लेकर अलग-अलग स्थानों पर खोने या नष्ट करने की बातें कही हैं। मोबाइल फोन की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। एसआईटी प्रमुख का कहना है कि फिलहाल छात्रा का बयान दर्ज नहीं हो सका है। उसकी सेहत सामान्य होने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे।

दुकान में विवाद के बाद युवक की हत्या

महाराष्ट्र का रहने वाला था मृतक, भांजे के साथ खरीददारी करने गया था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के मिसरोद में महाराष्ट्र से आए युवक की हत्या का मामला सामने आया है। वह नाबालिग भांजे के साथ किराना दुकान पर खरीददारी करने गया था। जहां युवक से उसका मामूली विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने अपने पास रखे छुरे से युवक पर वार कर दिए। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

टीआई रतन सिंह परिहार के मुताबिक 26 वर्षीय पवन गवई गांव मल्लापुर जिला नादुरा का रहने वाला था। उसकी बहन मिसरोद के जाटखेड़ी में रहती है। बहन से मिलने के लिए 14 फरवरी को भोपाल आया था। रविवार की रात को नाबालिग भांजे के साथ जाटखेड़ी की एक दुकान पर किराना सामान लेने पहुंचा था। यहां मोहल्ले में रहने वाला आरोपी बल्लू पहले से बैठा था।

मामूली कमेंट्स को लेकर शुरू हुआ था विवाद- उसने पवन पर कमेंट किया कि महाराष्ट्री यहां कैसे घूम रहा है। इस पर पवन ने जवाब दिया कि तुम से पूछकर थोड़ी आऊंगा। इसी बात पर आरोपी ने पहले पवन को चांटा मारा। बदले में पवन ने भी चांटा मार दिया। इससे गुस्साए आरोपी बल्लू ने अपने पास रखी छुरी को निकाला और पवन के सीने में एक गेहरा वार कर दिया।

ट्रक ने पूर्व सरपंच को रौंदा... 50 मीटर तक घसीटा

सतना-चित्रकूट स्टेट हाईवे पर पिछले टायर में फंसा, लोगों ने पीछा कर रोका

सतना (नप्र)। सतना-चित्रकूट स्टेट हाईवे पर सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक ने पूर्व सरपंच को कुचल दिया। वह ट्रक के पिछले टायर में फंसकर करीब 50 मीटर तक घिसटता गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। घटना सुबह लगभग 11 बजे कोठी के पास रोयनी मोड़ के पास हुई। ट्रक चित्रकूट से सतना की ओर जा रहा था। हादसे में मरने वाला अनूप सिंह (50) मनकहरी का रहने वाला था। वह इसी गांव का सरपंच रह चुका था। सैलून से शेविंग कराकर पैदल घर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना के बाद राहगीरों ने पीछा कर ट्रक को रुकवाया, लेकिन आरोपी ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने ही कोठी टीआई संतोष तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने भोपाल में सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ कर कहा

नवाचार सुशासन के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जनकल्याण को प्रोत्साहन दे रही है। पंजीयन विभाग के सायबर पंजीयन

- **सायबर पंजीयन कार्यालय से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को मिलेगा प्रोत्साहन**
- **मुख्तयारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पॉवर ऑफ अटार्नी जैसी 75 से अधिक सेवाओं का हो रहा है सायबर पंजीयन**
- **संपदा 2.0 को मिला है वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार**

कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है। संपदा-1.0 और संपदा 2.0 के बाद प्रदेश में सायबर पंजीयन की प्रक्रिया का आरंभ होना तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत है। मध्यप्रदेश तेजी से बदल रहा है। मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोन, मुख्तयारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर आफ अटार्नी, पार्टनरशिप डीड जैसी

75 से अधिक सेवाओं के लिए सायबर पंजीयन प्रारंभ किया है। राज्य सरकार के इस नवाचार से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है। यह नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारदर्शिता के मामले में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को पंजीयन भवन में सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद ये विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे होंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अंतरण के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो केवायसी सहित सभी कार्य होंगे, इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संपदा 2.0 के नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है। अब तक 14 लाख 95 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। राज्य सरकार ने 55 जिलों में सायबर तहसील परियोजना को लागू किया है, जिसमें राजस्व बंटवारा, नामांतरण की प्रक्रिया भी संपदा 2.0 से हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागीय अधिकारी सायबर पंजीयन सुविधा के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लक्ष्य पूरे करें।

उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 लागू किया। इससे चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल और पेपरलेस तरीके से पंजीकृत हो रहे हैं। कई दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनके लिए उप-पंजीयक कार्यालय भी नहीं आना पड़ता है। सबसे पहले गुना,हरदा, रतलाम और डिण्डौरी जिलों में नए ई-पंजीयन और ई-स्थम्पिंग सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। प्रदेश के नवाचारों को देशभर में सराहा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जारी इन नवाचारों का लाभ प्रदेश के नागरिकों को मिल रहा हैं। पंजीयन से जुड़े कार्यों को त्रूटि रहित पूरा करने के लिए प्रदेशभर के 14 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री अमित राठौर, प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह, महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री अमित तोमर उपस्थित रहे। कार्यक्रम से जिलों के अधिकारी, बैंककर्मी और लाभार्थी वर्चुअली जुड़े।

कान्हा में मातम, मां से बिछड़े नर तेंदुए की नहीं बच सकी जान

मंडला (नप्र)। कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही परिक्षेत्र में घायल अवस्था में मिले एक नर तेंदुए की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने त्वरित रेस्क्यू कर प्राथमिक उपचार दिया था और उसे मुक्की अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं।

एनीकट नाला के पास मिला था घायल- जानकारी के अनुसार, शनिवार को सरही परिक्षेत्र के दलदला बीट कक्ष क्रमांक 729, एनीकट नाला (बेंदीवारे दलदला वनमार्ग) के पास तेंदुआ घायल हालत में पड़ा मिला। गश्ती दल ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद भुआ बिछिया से वन अमला और जबलपुर स्थित वाइल्डलाइफ और फॉरेंसिक स्कूल से पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके पर ही तेंदुए का उपचार किया। हालत गंभीर होने पर

उसे रेस्क्यू वाहन से मुक्की अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

एनटीसीए की गाइडलाइन में हुआ पोस्टमार्टम- रविवार को तेंदुए का पोस्टमार्टम हुआ। नई दिल्ली और मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया। पोस्टमार्टम डॉ. अमोल रोकड़े, डॉ. दीपाली परते और डॉ. विशाल उद्दे की टीम ने किया। प्रारंभिक जांच में तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित पाए गए। प्रथम दृष्टया उसकी मौत स्वाभाविक कारणों से होना प्रतीत हुई है।

एसओपी के तहत किया अंतिम संस्कार- निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उप संचालक (कोर) पी.के. वर्मा, सहायक संचालक बंजर सूरज सिंह सेन्द्राम, तहसीलदार भुआ बिछिया शंकरलाल मरावी, सरपंच किसली भिलवानी डीलन सिंह सैयाम, एनटीसीए प्रतिनिधि ओमकार नर, मानक वन्यप्राणी अभिरक्षक चंद्रेश खरे सहित वन परिक्षेत्र सरही का स्टाफ मौजूद रहा।

बीएलओ से सीईओ तक सभी इलेक्शन कमीशन हैं, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण : पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रावत

राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आयोगों का कहा जाता है वर्ल्ड बैंक : श्रीवास्तव

भोपाल। बीएलओ से लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक सभी इलेक्शन कमीशन हैं। निर्वाचन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने यह बात सोमवार को प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में कही। श्री रावत ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन में स्थानीय निर्वाचन की भूमिका' विषय पर बोलते हुए कहा कि इस पर चर्चा 2015 में शुरू हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें सहमति व्यक्त की गयी थी।

राज्य निर्वाचन आयोग जरूरी- रावत ने कहा कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' को लागू करने पर भी राज्य निर्वाचन आयोग जरूरी होंगे। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव इनके माध्यम ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का ड्राफ्ट जरूर मंजूर होगा। श्री रावत ने माडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।

चुनाव, चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा का हो या पंचायत का- पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने 'स्थानीय निर्वाचन में सुधार की चुनौती' विषय पर कहा कि 'हर वोट-हर निकाय' महत्वपूर्ण है। श्री परशुराम ने कहा कि चुनाव, चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा का हो या पंचायत का। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में प्रिपेयर, प्रिपेयर और प्रिपेयर के फार्मूले का हमेशा पालन करना चाहिए। नवीनतम तकनीकों के उपयोग से घबराना नहीं चाहिए। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग तुलनात्मक रूप से अधिक अधिकार संपन्न है।

नरेन्द्र कुमार सिंह ने 'जमीनी लोकतंत्र में पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव ' विषय पर 1952 के प्रथम लोकसभा निर्वाचन से लेकर वर्तमान लोकसभा निर्वाचन तक के अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सन 1977 के चुनावों ने सिद्ध कर दिया कि देश में मतदाता बहुत हुए जागरूक हैं और लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। श्री सिंह ने बताया कि ब्रिटेन में वर्ष 1928 में सभी को मताधिकार मिला जबकि भारत ने स्वतंत्र होने के साथ ही सभी को मताधिकार (युनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज) दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने 'स्थानीय निर्वाचन में न्यायालीन सबक' विषय पर विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि संविधान एक जीवंत ग्रंथ है। उन्होंने निर्वाचन से संबधित कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोगों की पिछली बैठक में मध्यप्रदेश को राज्य निर्वाचन आयोगों का वर्ल्ड बैंक कहा गया। उन्होंने श्री रावत, श्री परशुराम, श्री सिंह और श्री सेठ के द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख किया। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यह समारोह विशेष इसलिए भी है, क्योंकि सभी उपस्थित अतिथियों ने निर्वाचन की यात्रा को प्रेरणा और दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल टेक्नॉलोजी में श्री परशुराम ने मध्यप्रदेश को पॉयनियर बना दिया है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मैदानी अधिकारियों ने आयोग में नवाचारों को लागू करने में निष्ठा और मनायोग से काम किया। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अतिथियों ने आयोग के 'निर्वाचन साहित्य ई-बुक' का विमोचन और 'प्रेक्षा मोबाइल ऐप' का शुभारंभ किया। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलेक्टर्स, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया।

राजस्थान के ऊंट-भेड़ों के लिए मप्र में नया कॉरिडोर

चालीस साल पुराने नियम में किया बदलाव, एमपी होकर जा सकेंगे छत्तीसगढ़

भोपाल (नप्र)। मोहन सरकार ने राजस्थान के ऊंटों, भेड़ों और अन्य जानवरों के लिए नया कॉरिडोर खोला है। चालीस साल बाद किए गए बदलाव के बाद अब एमपी में पांच मार्गों से राजस्थान के ऊंटों, भेड़ों की आवाजाही हो सकेगी। मोहन सरकार द्वारा घोषित किए गए नए कारिडोर से होकर राजस्थान के जानवर यहां चराई के साथ छत्तीसगढ़ तक जा सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने राजस्थान के पशुपालकों को राहत देते हुए भेड़, ऊंट आदि पशुओं की एमपी में चराई के लिए पांचवां मार्ग भी मंजूर कर दिया है। इस मार्ग से राजस्थान के पशुपालक अपने पशुओं को लेकर मध्यप्रदेश में प्रवेश कर चराई कर सकेंगे। यह पांचवां मार्ग दमोह, नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, डिंडौरी और अमरकंटक होते हुए

छत्तीसगढ़ की सीमा तक राजस्थान के पशुओं को निकासी देगा। इसके पहले एमपी सरकार ने अन्य राज्यों के पशुओं को चराई की सुविधा देने के लिए वर्ष 1986 में चराई नियम बनाए थे। इसी नियम के अंतर्गत अब पांचवां मार्ग घोषित किया गया है। इसके पहले प्रदेश में चार मार्ग पहले से अधिकृत थे, जिनसे राजस्थान के पशुपालक अलग-अलग जिलों से होकर एमपी में प्रवेश करते थे। अब नए मार्ग के जुड़ने से पशुपालकों को आवाजाही और चराई में सुविधा मिलेगी।

अब तक ये मार्ग तय थे, जो एमपी की सीमा से गुजरते हैं

सवाई माधोपुर (राजस्थान) से माली घाट, चंबल नदी होते हुए श्योपुर, कराहल, जोहरी, शिवपुरी, मोहन्ना, ग्वालियर और भिंड होकर यूपी के इटावा में निकासी।

शाहबाद (राजस्थान) से बमोरी (गुना), गुना, ईसागढ़, चंदेरी होकर यूपी के ललितपुर में निकासी।

इकलेरा (राजस्थान) से भोजपुर, खिलचीपुर, राजगढ़, सितोलिया, लटेरी, सिरोंज, चौराहा, सारस, बहेड़ी, ढाकेनी, चंदेरी होकर यूपी के ललितपुर में निकासी।

गुजरात के जो पशु महाराष्ट्र के अमरावती की ओर जाते हैं, वे झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर होकर महाराष्ट्र की सीमा में जाते हैं।